सर्वहारा दृष्टिकोण

डिजिटल संस्करण
इंटरनेट के जरिये वितरण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) SUCI (C) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-41 अंक 8 | 22 अप्रैल से 6 मई 2026 | मुख्य संपादक: कॉमरेड प्रभास घोष | कुल पृष्ठ : 8 | मूल्य : 4 रुपये | पृष्ठ 1

कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षाओं से...

"मार्क्सवाद-लेनिनवाद इस युग का सर्वोच्च आदर्श, सर्वोच्च विचारधारा है। इस विचारधारा में इस युग की नीति-नैतिकता की सबसे उन्नत और सर्वश्रेष्ठ अवधारणाएं निहित हैं।"(वर्तमान स्थिति और जनआंदोलन में मुख्य खतरा)

"यह पार्टी भारत की खास परिस्थिति में मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सही प्रयोग के जरिये बिल्कुल एक नए मॉडल पर तथा नई विचारधारा को लेकर बनी है। इसके बनने की पद्धति और प्रक्रिया औरों से पूर्णतः भिन्न है।"(एक महान क्रांतिकारी चरित्र को श्रद्धांजलि)

"क्रांतिकारी उद्देश्यमुखिता के लक्ष्य से जब सर्वहारा वर्ग की पार्टी निरुपाय होकर जनता के साथ खड़ी रहने के लिए चुनावी लड़ाई लड़ने जाती है, तब वह जनता की एक क्रांतिकारी राजनीतिक लाइन के आधार पर ही ऐसा करती है। सीटें जीतने के लिए वह भी भरसक कोशिश करती है। लेकिन उसके उद्देश्य का केन्द्र बिन्दु येन-केन-प्रकारेण ज्यादा

से ज्यादा सीटों पर कब्जा करना कतई नहीं होता। क्रांतिकारी पार्टी के लक्ष्य का मुख्य केन्द्र बिन्दु होता है जनता की क्रांतिकारी राजनीतिक लाइन के आधार पर जनता को चुनावी लड़ाई लड़ना सीखाना। ऐसा करते हुए अगर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत भी जाये, तो बेहतर है। अगर एक भी सीट न मिले, तो न सही। अगर हम दस सीटों की रक्षा कर पाये, तो 10 ही सही। लेकिन उसके लक्ष्य का मुख्य केन्द्र बिन्दु येन-केन-प्रकारेण, जिस किसी भी हथकंडे से कुछ सीटें हथियाना कदापि नहीं है।"(मजदूर आंदोलन में एकता बनाये और नेतृत्व कायम करने के प्रसंग में)

महान 24 अप्रैल जिन्दाबाद!

इस साल 24 अप्रैल को हम देश के सर्वहारा वर्ग के अगुआ दस्ता सोशलिस्ट यूनिटी सेण्टर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) की स्थापना की 78वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। इसकी स्थापना, संचालन तथा मार्गदर्शन हमारे प्रिय नेता, शिक्षक, पथप्रदर्शक और इस युग के एक अग्रणी मार्क्सवादी चिंतक कॉमरेड शिवदास घोष ने किया था। हम देश और दुनिया के जिन हालात में पार्टी का स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं, वे संक्षेप में कहें तो, बड़े भयानक है।

दुनिया समझ रही है कि जायोनी इजरायल और अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा ईरान पर किये जा रहे क्रूर बर्बरतापूर्ण सैन्य हमले का मकसद ईरान को घुटने टेकने के लिए मजबूर करना और मध्य-पूर्व पर अमेरिकी साम्राज्यवादियों का पूर्ण नियंत्रण कायम करना है। इससे पहले, अमेरिकी साम्राज्यवाद ने वेनेजुएला के तेल उद्योग पर अपना मालिकाना कायम करने के लिए सैन्य हस्तक्षेप के जरिये वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष का अपहरण कर लिया। पूरी दुनिया देख रही है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद के सीधे समर्थन से जायोनी इजरायल ने गजा पट्टी को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। उसने गजा में भारी तबाही मचायी, लाखों बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की हत्या की और मकानों, अस्पतालों व शिक्षण संस्थानों को धूल में मिला दिया। देखा जा रहा है कि समाजवादी खेमे की गैरमौजूदगी की वजह से अमेरिकी साम्राज्यवादी दरिन्दे स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का सरेआम उल्लंघन करते हुए दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में एक के बाद एक युद्ध छेड़ रहे हैं। इस प्रकार, मानव सभ्यता एक अभूतपूर्व खतरे और अवर्णनीय दुख-तकलीफों का सामना करने को मजबूर है।

हमारे देश में पूंजीपतियों के बेलगाम शोषण की वजह से देश के लोगों की क्रय शक्ति लगभग खत्म होने को है। लाखों कल-कारखाने बंद हैं। महंगाई ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। इसके साथ ही देश का आम अवाम बेरोजगारी की लगातार बढ़ती समस्या, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, शिक्षा के व्यापारीकरण व साम्प्रदायीकरण तथा नैतिक गिरावट के अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। सर्वविदित है कि कांग्रेस लम्बे समय से इस देश के पूंजीपतियों की सेवा करती रही है। वर्तमान में इसी की निरंतरता में देशी-विदेशी पूंजीपतियों के हित में केन्द्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने घोर मजदूर-विरोधी चार श्रम संहिताएं लागू कर न्यूनतम मजदूरी व सुरक्षा सहित मजदूरों के अधिकारों को छीनने का काम किया है। स्थायी रोजगार की अवधारणा को ही खत्म किया जा रहा है। इसके अलावा, भारतीय एकाधिकारी पूंजीपतियों के हित साधने के लिए केन्द्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने किसानों, मछुआरों, पशुपालकों सहित आम लोगों की रोजी-रोटी के हितों की बलि देते हुए अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौता किया है। इससे खाद्यान्न, दूध और दुग्ध उत्पादों के बाजार पर अमेरिकी बहुराष्ट्रीय पूंजी का कब्जा हो जायेगा और देश के किसान बर्बाद हो जायेंगे। नतीजतन, इस देश के किसानों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। साथ ही केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर एक ओर तो शिक्षा का पूर्ण निजीकरण शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा के मूल तत्व

(शेष पृष्ठ 2 पर)

चुनाव या छलावा : कुछ बातें, कुछ विरोध

एक अभूतपूर्व स्थिति में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। मतदान के माध्यम से लोगों के पास जो कुछ भी लोकतांत्रिक अधिकार बचा था, वह भी आज गंभीर खतरों से रूबरू है।

मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) के बाद पिछले 28 फरवरी, 2026 को राज्य में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हुई है। इसमें देखा गया है कि प्रकाशित 'प्रारूप मतदाता सूची' में राज्य के जुड़ावहीन या 'अनमैप्ड' मतदाताओं की संख्या नगण्य होने के बावजूद, अंतिम सूची में साढ़े पांच लाख नाम हटा दिये गए हैं और साठ लाख से अधिक नामों को 'अंडर एडजुडिकेशन' (विचाराधीन) बताकर अनिश्चित घोषित कर दिया गया है। जिन विधानसभा क्षेत्रों में अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या अधिक है, वहां विचाराधीन मतदाताओं की संख्या भी अधिक थी। अंततः विचाराधीन मामलों का निपटारा हुआ और साठ लाख से अधिक विचाराधीन मतदाताओं में से सत्ताईस लाख मतदाताओं के नाम काट दिये गए हैं। इनमें से अधिकतर वैध मतदाता हैं और इस वोट कटौती का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अपना अपराध जानने का अवसर भी नहीं है। अब वे फिर से कड़ी धूप में शहर आकर ट्रिब्यूनल में अपील के लिए कतारों में खड़े हैं।

समग्र रूप से विचार करें, तो यह प्रक्रिया निस्संदेह अत्यंत सुनियोजित है। पहले 'एसआईआर' के नाम पर बहुत कम समय में इस विशाल कार्य को संपन्न करने के लिए बीएलओ सहित अधिकारियों को बाध्य किया गया। वोटर कार्ड और आधार कार्ड जैसे प्रचलित प्रमाणों को छोड़कर ऐसे दस्तावेज मांगे गए, जो अधिकांश मामलों में सुलभ नहीं हैं। फिर समय-समय पर अलग-अलग दस्तावेजों के नाम पर लोगों को भ्रमित किया गया। चुनाव आयोग ने इस बात की घोषणा की थी कि जिनका नाम 2002 की मतदाता सूची में शामिल है, उन्हें कोई प्रमाण नहीं देना होगा। उस निर्देश के विपरीत जाकर 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' के नाम पर एक करोड़ से अधिक लोगों को सुनवाई की कतारों में खड़ा कर दिया गया। फिर साठ लाख लोगों को 'विचाराधीन' के रूप में चिन्हित किया गया। अंत में सत्ताईस लाख विचाराधीन नाम काट दिये गए। अगर एसआईआर के पहले चरण से गणना करें, तो राज्य में हटाये गए मतदाताओं की संख्या इक्यानवे लाख है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बाहर रखकर ही चुनाव होने जा रहे हैं। इतने लोगों को मतदान से वंचित कर जो चुनाव हो रहा है, स्वाभाविक रूप से उसकी वैधता पर सवाल उठे हैं।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

जंतर-मंतर पर उमड़ा देशभर के युवाओं का सैलाब

ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के शुभारंभ पर आयोजित युवा महापंचायत ने फूंका आंदोलन का बिगुल

नई दिल्ली: 11 अप्रैल को राजधानी के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ आर्गेनाइजेशन (एआईडीवाईओ) के तत्वावधान में आयोजित एक विशाल युवा महापंचायत में देश के कोने-कोने से आये सैकड़ों युवाओं और जागरूक नागरिकों ने हिस्सा लिया। यह महापंचायत भारतीय नवजागरण के महान मनीषी व समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की 200वीं जन्म वार्षिकी के अवसर पर आयोजित की गई। इसमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसी समस्याओं के खिलाफ एक निर्णायक संघर्ष का आह्वान किया गया।

नई दिल्ली: बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसी समस्याओं के खिलाफ एआईडीवाईओ द्वारा जंतर मंतर पर आयोजित युवा महापंचायत के बाद प्रदर्शन करते हुए देशभर से आये युवा प्रतिनिधि

शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र के प्रख्यात वक्ताओं ने महापंचायत को संबोधित करते हुए केंद्र व राज्य सरकारों की नीतियों पर तीखे सवाल उठाए।

सभा को संबोधित करते हुए प्रो. अतुल सूद (जेएनयू) ने कहा कि एक तरफ सरकारें रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षा नीतियों के माध्यम से छोटी उम्र से ही छात्र-नौजवानों में सवाल करने की प्रवृत्ति को ही खत्म कर रही हैं। नतीजतन, आंदोलन खड़ा करना तो दूर की बात, समाज में अन्याय के

(शेष पृष्ठ 5 पर)

चुनाव या छलावा...

(पृष्ठ 1 का शेष)

कई लोग कह रहे हैं कि यह चुनाव एक छलावा है। फिर कई लोगों का मानना है कि कम से कम उन राजनीतिक पार्टियों को, जिनका लक्ष्य केवल सत्ता हासिल करना या उसके करीब पहुंचना नहीं है, जो राजनीति में विचारधारा की बात करती हैं, उन्हें इस चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। क्योंकि इस चुनाव में भागीदारी का अर्थ है इस अन्यायपूर्ण और अनैतिक चुनाव को वैधता प्रदान करना। पिछले चार महीनों से भी अधिक समय से लाखों लोगों की अकथनीय दुर्दशा, दुख-तकलीफों और मौत को देखकर संवेदनशील लोगों ने एसआईआर और उसके आधार पर होने वाले चुनाव के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त किया है। यह आवेग अत्यंत तर्कसंगत है। लेकिन साथ ही, इसे केवल भावना नहीं, बल्कि तर्क की कसौटी पर भी देखना आवश्यक है।

संसदीय लोकतंत्र में चुनाव एक बुर्जुआ (पूंजीवादी) गतिविधि है। वर्ग-विभाजित समाज में दमनकारी पूंजीवादी राज्य को वैधता देने के लिए ही यह चुनाव कराया जाता है। महान लेनिन के अनुसार, संसदीय चुनाव यह निर्धारित करता है कि एक निश्चित अंतराल के बाद पूंजीपतियों की ओर से जनता पर कौन शासन करेगा। फिर भी, लंबे समय तक इन चुनावों में न केवल पूंजीपतियों की पोषित पार्टियां, बल्कि सर्वहारा वर्ग की सही कम्युनिस्ट पार्टी भी भाग लेती रही है, हालांकि दोनों के दृष्टिकोण अलग हैं।

अब प्रश्न यह है कि जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहती है, जबकि भाजपा एसआईआर सहित विभिन्न राजकीय तिकड़मों के माध्यम से राज्य की सत्ता हथियाना चाहती है। कहने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस भी भाजपा की तरह ही पूंजीपति वर्ग की अत्यंत विश्वसनीय पार्टी है, जो राज्य में अपना खोया हुआ गौरव वापस पाना चाहती है। चौंतीस वर्षों तक शासन की अभ्यस्त रही माकपा यानी सीपीआई (एम) सत्ता खोने के दर्द को भूलने के लिए कभी मुस्लिम साम्प्रदायिक संगठन आईएसएफ, तो कभी कांग्रेस से सांठगांठ कर किसी तरह संसदीय व्यवस्था में प्रासंगिक बने रहना चाहती है; भाकपा-माले (लिबरेशन) सहित अन्य सहयोगी दल भी उनके पीछे चल रहे हैं। जहां तक एसयूसीआई (सी) की बात है, यह जन मुद्दों को लेकर सड़कों पर लड़ती है और खुद को सही कम्युनिस्ट पार्टी मानती है। 'डिलीटेड' के रूप में चिन्हित इन वंचित, असहाय और संकटग्रस्त लोगों के प्रति सहानुभूति रखने वाले जो लोग मानते हैं कि इस चुनाव का बहिष्कार होना चाहिए–उनकी अपेक्षाएं भी एसयूसीआई (सी) से ही हैं।

भावनाएं अनमोल हैं, लेकिन उन्हें भी तर्क की कसौटी पर परखना होता है। समाचारों के अनुसार, एसआईआर के बाद असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में रिकॉर्ड मतदान हुआ है। यानी लोगों के मन में चाहे जो भी आक्रोश हो, उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में चुनाव को ही चुना है। एसआईआर के इस भयानक अनुभव का सामना करने के बाद राज्य के आम लोगों की मुख्य मांग क्या है? विभिन्न सर्वेक्षणों में जो पाया गया है, वह यह है कि आम आदमी अपना मताधिकार चाहता है, वह वोट देना चाहता है। वह वोट देकर ही विरोध करना चाहता है, बहिष्कार नहीं। मालदा, दिनाजपुर या मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज, सूती, रघुनाथगंज, लालगोला जैसे क्षेत्रों में, जहां मतदाता सूची से 70% या उससे अधिक नाम हटा दिये गए हैं, वहां जितना भी संगठित विरोध हुआ है, वहां आक्रोशित जनता का कहना है कि सभी के नाम मतदाता सूची में शामिल किये जाएं और उन्हें वोट देने का अवसर मिले। इस चिलचिलाती धूप में जो व्यक्ति ट्रिब्यूनल की कतार में खड़ा है, उसकी आंखों के आंसू भी यही गुहार लगा रहे हैं कि उसे वोट देने का मौका दिया जाए। इस मतदान के साथ ही इस देश में उसकी नागरिकता और उसके अस्तित्व का अधिकार जुड़ा हुआ है।

इस देश में संसदीय लोकतंत्र इतना गहरा है, प्रचारों के शोर में 'पवित्र' चुनाव ने लोगों को ऐसा मुग्ध कर रखा है और 'महान' संविधान की रक्षा की भावना भूखे-नंगे लोगों को भी इस कदर झकझोर देती है कि गरीब श्रमजीवी जनता इसके विकल्प के बारे में सोच ही नहीं पाती। मीडिया के धुआंधार प्रचार के बावजूद, एक क्रांतिकारी पार्टी चुनाव में भाग लेकर संसदीय लोकतंत्र की खोखली प्रकृति तथा लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों और आजीविका की बात जनता के सामने रखकर उसे जागरूक करती है। जहां अधिकतर लोग राज्य के प्रचार से मुग्ध होकर या भ्रमित होकर संसदीय चुनावों में डूबे हुए हैं, वहां चुनाव में हिस्सा न लेकर कोई जिम्मेदार क्रांतिकारी पार्टी निहत्थे लोगों को भाजपा की जहरीली सांप्रदायिकता और कॉर्पोरेट शोषकों के बीच कैसे छोड़ सकती है?

प्रख्यात मार्क्सवादी दार्शनिक और सर्वहारा वर्ग के महान नेता शिवदास घोष ने दिखाया है: "इलेक्शन एक बुर्जुआ राजनीति है। अगर जनता में राजनीतिक चेतना न हो, मजदूर वर्ग का संघर्ष और वर्गीय संगठन न हो, जन आंदोलन न हो, जनता की संगठित शक्ति न हो, तो उद्योगपति, बड़े व्यापारी और प्रतिक्रियावादी ताकतें भारी पैसा बहाकर और समाचार माध्यमों की मदद से जो हवा बनाती हैं, जनता उसमें तिनके की तरह बह जाती है।" (1974 के शिक्षण शिविर में भाषण)।

इस भारी तूफान के बीच क्रांतिकारी पार्टी एक नाविक की तरह पतवार थामे रहती है। इसलिए चुनाव बहिष्कार या चुनाव में भाग लेकर छलावापूर्ण चुनाव को वैधता प्रदान करने का विमर्श यहां बेमानी है, क्योंकि राज्य किसी की वैधता की परवाह नहीं करता। सवाल जनता के साथ खड़े होने का है। मतदान का बहिष्कार कर चुनावी मैदान छोड़ना नहीं, बल्कि चुनाव में रहकर ही 'एसआईआर' के नाम पर चोर दरवाजे से एनआरसी लागू करने की साजिश के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने की तैयारी करनी है।

इसलिए शिवदास घोष ने बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया है: "...हम चुनाव में हैं, क्योंकि चुनाव के माध्यम से संसदीय राजनीति की गरमाहट जनमानस को प्रभावित करती है। जनता चाहे पसंद करे या न करे, उसे खींच लाया जाता है और जनता आ जाती है।... जब जनता यह समझ जाएगी कि चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है, जब इस चेतना के आधार पर जनता संगठित होकर चुनाव का बहिष्कार करेगी–'नेगेटिव' यानी नकारात्मक बहिष्कार नहीं बल्कि 'पॉजिटिव' यानी सकारात्मक बगावत की स्थिति में पहुंच जाएगी–तभी चुनाव अप्रभावी हो सकता है, अन्यथा जनता बार-बार चुनाव में फंसती है। और जनता के साथ रहने के लिए चाहे क्रांतिकारी हों या गैर-क्रांतिकारी, सभी को चुनाव में जाना पड़ता है, सच्चे क्रांतिकारियों को भी जाना पड़ता है।"(सर्वहारा क्रांतिकारी पार्टी और कार्यकर्ताओं की भूमिका के कुछ पहलू)।

इस संदर्भ में महान लेनिन की शिक्षा को याद करना आवश्यक है। लेनिन, जिन्होंने दुनिया की पहली समाजवादी क्रांति का नेतृत्व किया था, ने 106 साल पहले, 1920 में दुनिया के मेहनतकशों के सामने जो सीख रखी थी, वह आज भी प्रासंगिक है:

"संसदीय चुनावों में और संसदीय मंच के संघर्ष में भाग लेना क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग की पार्टी के लिए अपरिहार्य है, विशेष रूप से अपने वर्ग के पिछड़े तबके को शिक्षित करने और अविकसित, दबे-कुचले और अज्ञानी ग्रामीण जनसमूह को जागरूक करने के उद्देश्य से। जब तक आपमें बुर्जुआ संसदों और अन्य प्रतिक्रियावादी संस्थाओं को खत्म करने की शक्ति नहीं है, तब तक आपको उनके भीतर काम करना चाहिए, क्योंकि वहीं आपको वे श्रमिक मिलेंगे, जो पुजारियों द्वारा ठगे गए हैं और ग्रामीण जीवन की स्थितियों से जड़ हो चुके हैं; अन्यथा आप केवल बातें बनाने वाले बनकर रह जाने का जोखिम उठाते हैं।" ('वामपंथी' कम्युनिज्म, एक बचकाना मर्ज)।

इसलिए इस सुनियोजित जन-उन्माद के समय में जनता के साथ रहकर ही एसआईआर-विरोधी संघर्ष की तैयारी करनी चाहिए ताकि चुनाव के बाद इस उपेक्षित (!) जनता को साथ लेकर लड़ाई लड़ी जा सके। इस कठिन समय में हमें सतर्क रहना चाहिए ताकि कोई हमें जन-विच्छिन्न और केवल बातें करने वाला बतोलेबाज कहकर इल्जाम ना लगा सके। ❑

उज्जैन की भौगोलिक स्थिति और जीएमटी के बजाय एमएसटी का विरोध

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के उज्जैन की भौगोलिक स्थिति और जीएमटी के स्थान पर महाकाल मानक समय (एमएसटी) की शुरुआत के दावे का विरोध करते हुए ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी (एआईएसईसी) के महासचिव प्रो. तरुण कांति नस्कर ने 8 अप्रैल को जारी बयान में कहा:

केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान का हालिया दावा कि "उज्जैन वह जगह है, जहां भूमध्य रेखा और कर्क रेखा मिलती हैं" मौलिक रूप से गलत है और बुनियादी विज्ञान के प्रति चौंकाने वाली अवहेलना का प्रतिनिधित्व करता है। भौगोलिक और भौगोलिक रूप से, यह कथन असंभव है। भूमध्य रेखा (0अक्षांश) और कर्क रेखा (लगभग 23.5 उत्तर अक्षांश) पृथ्वी के गोले पर समानांतर पूर्व-पश्चिम वृत्त हैं। क्योंकि वे समानांतर हैं, वे कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकतीं। इसके अलावा, जबकि कर्क रेखा मध्य भारत से होकर गुजरती है, विषुवत रेखा पूरी तरह से देश के दक्षिण में स्थित है। शिक्षा मंत्री के लिए सार्वजनिक मंच पर माध्यमिक-विद्यालय भूगोल को दरकिनार करना अत्यधिक चिंताजनक है। हम उस ऐतिहासिक संदर्भ से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि वैश्विक मानकीकरण की आवश्यकता से पहले, प्राचीन सभ्यताओं के लिए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों के आधार पर अपने स्वयं के स्थानीय प्रधान मध्याह्न रेखाओं की स्थापना करना ठीक वैसे ही सार्वभौमिक रूप से आम था, जैसे यूनानियों ने अलेक्जेंड्रिया का इस्तेमाल किया, इस्लामी विद्वानों ने बगदाद का और फ्रांसीसियों ने पेरिस का। इसी तार्किक परंपरा में, सूर्य सिद्धांत जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों ने उज्जैन को अपनी समन्वय प्रणाली की प्रमुख मध्याह्न रेखा माना। हालांकि प्राचीन खगोल विज्ञान के इस समृद्ध, स्थानीयकृत इतिहास को स्वीकार करना आज इसे स्पष्ट रूप से झूठे आधुनिक भौगोलिक दावे खोज कर उचित ठहराने से पूरी तरह अलग है।

तथ्य यह है: चूंकि विभिन्न देशांतरों वाले पृथ्वी के सभी स्थानों में अलग-अलग समय होता है, इसलिए किसी को एक विशेष देशांतर रेखा को आधार के रूप में तय करना होगा और उस संबंध में अन्य सभी स्थानों के समय को मापना होगा। यह कोई भी मनमानी रेखा हो सकती है और इस रेखा का कोई विशेष महत्व नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि ऐतिहासिक रूप से ग्रीनविच के देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस रेखा के रूप में अपनाया गया है।

इसलिए यह स्पष्ट है कि श्री धर्मेंद्र प्रधान का एकमात्र उद्देश्य जीएमटी के स्थान पर 'महाकाल मानक समय' (एमएसटी) लागू करने के लिए बिना किसी वैज्ञानिक आधार के उज्जैन की भौगोलिक स्थिति को महिमामंडित करना है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने हमारा देश हास्यास्पद बन जाएगा।

हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस मंसूबे का विरोध करते हैं और इस बयान को तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं।

महान 24 अप्रैल...

(पृष्ठ 1 का शेष)

वैज्ञानिक तर्कसंगतता को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में अमेरिकी और इजरायली जंगखोरों द्वारा ईरान पर एकतरफा हमला करने की वजह से तेल समेत आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल आने की आशंका है। इसी अवसर का लाभ उठाते हुए रसोई गैस की कीमत में एकाएक 60 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गयी है। इतना ही नहीं, वे जनवादी आन्दोलनों को कुचलने के लिए और अधिक कठोर कानून बना रहे हैं। यह सब कुछ भाजपा नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय शासक पूंजीपति वर्ग के हित साधने के लिए किया जा रहा है।

जब केन्द्र और राज्यों में पूंजीपतियों की हितैषी सत्ताधारी पार्टियों के खिलाफ एक जोरदार वामपंथी आन्दोलन खड़ा करने की जरूरत थी, तब सीपीआई (एम) सहित वामपंथी के रूप में जाने जाने वाली पार्टियों की भूमिका काफी अफसोसजनक है। जिस कांग्रेस सरकार के खिलाफ लम्बी लड़ाई लड़कर वामपंथी आन्दोलन को मर्यादा और गौरव प्राप्त हुआ था, आज महज कुछ सीटें पाने के लिए ये पार्टियां देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोंटने वाली तथा विभिन्न दमनकारी कानून थोपने वाली और देश के विभिन्न स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे करवाने वाली उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन कायम किये हुए हैं और उसे जनवादी और धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में पेश कर रही हैं। स्वाभाविक है कि इससे वामपंथ की महान विचारधारा और उसकी गरिमा को चोट पहुंची है।

लेकिन गहन संकटों, गंभीर समस्याओं और दिक्कतों-परेशानियों से घिरे लोगों के जीवन की उपरोक्त दुखद तस्वीर के अलावा एक दूसरी सुखद तस्वीर भी है। वह यह है कि सभी साम्राज्यवादी-पूंजीवादी देशों में न केवल युद्ध के खिलाफ, बल्कि पूंजीवादी शोषण के खिलाफ भी आन्दोलनों की लहरें उमड़ रही हैं। हमारे देश में भी, समय-समय पर जन असंतोष का छिटपुट उभार देखा जा रहा है। लोग हर जगह विरोध कर रहे हैं। उनमें बदलाव की चाहत बलवती हो रही है। ऐसे में महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष की चेतावनी याद आती हैं। उन्होंने कहा था, "समाज में मजदूर-किसान व शोषित जनता के असंतोष को केन्द्रकर क्रांति बार-बार लहर पर लहर की तरह उमड़-घुमड़कर आना चाहेगी, लहर पर लहर की तरह फट पड़ना चाहेगी। समाज का अंदरूनी द्वन्द्व बार-बार उफन-उफनकर दस्तक देना चाहेगा कि यह स्थिति आमूल-चूल बदलनी चाहिए। लोगों के दिलो-दिमाग से, लोगों से अपील करना चाहेगी कि मुझे क्रांति चाहिए। लेकिन क्रांति तब तक नहीं होगी, बार-बार वापस लौट जायेगी, गुमराह होकर भटक जायेगी, बार-बार उससे प्रतिक्रिया को फायदा पहुंचेगा, क्रांति नहीं होगी, जब तक कि क्रांति का नेतृत्व करने लायक पर्याप्त ताकत के साथ क्रांतिकारी पार्टी उभरकर नहीं आ जाती।" स्वाभाविक रूप से ऐसे में जरूरत है मार्क्सवाद-लेनिनवाद से लैस ताकतवर सर्वहारा क्रांतिकारी पार्टी के उभार की। हमारी पार्टी केन्द्र और राज्य सरकारों की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जन आन्दोलन और वर्ग संघर्ष गठित करने के मकसद से जनता की अपनी राजनैतिक शक्ति जन कमेटियां बनाने में लगी हुई है। मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष की क्रांतिकारी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर इस संघर्ष के जरिये हमने अनेक मांगें हासिल की हैं।

हालात का तकाजा है कि हम सब मिलकर समाज के क्रांतिकारी परिवर्तन के मद्देनजर पूंजीवाद के खिलाफ जन आंदोलन और वर्ग संघर्ष को ताकतवर बनायें। ऐसे में, शोषित-पीड़ित लोगों की एकता और पूंजीवाद के खिलाफ एकजुट आंदोलन खड़ा करने के लिए लोगों को आगे आने की जरूरत है। ऐतिहासिक 24 अप्रैल एक बार और इस ऐतिहासिक आह्वान को दोहराता है।

सुधारवाद-संशोधनवाद के खिलाफ लेनिन का संघर्ष था युगांतकारी संघर्ष

— लेनिन स्मृति दिवस पर कॉमरेड प्रभास घोष

विश्व सर्वहारा वर्ग के महान नेता, शिक्षक और दुनिया की पहली समाजवादी क्रांति व राजसत्ता के शिल्पी कॉमरेड वी आई लेनिन की 102री बरसी पर एसयूसीआई (कम्युनिस्ट), पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी द्वारा 21 जनवरी को उत्तरी कोलकाता के वीरेंद्र मंच सभागार में एक सभा आयोजित की गयी। सभा की अध्यक्षता पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड ध्रुवज्योति मुखर्जी ने की।

पार्टी के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष मुख्य वक्ता थे। उस दिन की चर्चा को हम किस्तों में प्रकाशित कर रहे हैं। प्रकाशन से पहले कॉमरेड प्रभास घोष ने इसे संपादित और परिष्कृत किया है—सम्पादक, सर्वहारा दृष्टिकोण।

हम आज महान लेनिन के प्रति श्रद्धांजलि देने और उनकी अमूल्य क्रांतिकारी शिक्षाओं को याद करने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं।

महान लेनिन के बारे में विश्व साम्यवादी आंदोलन के महान नेता स्तालिन, माओ त्से-तुंग और शिवदास घोष के छात्र के रूप में मैंने जो कुछ समझा है, उसके आधार पर मैं कुछ बातें कहूंगा। महान लेनिन को समझने के लिए उनके एक ऐतिहासिक कथन का गूढ़ अर्थ समझना जरूरी है, जिसे मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं। उन्होंने कहा था कि युग-युग में जिन्होंने मानव जाति की मुक्ति के लिए संघर्ष किया है, शोषक वर्ग ने उनका दमन-उत्पीड़न किया है, उनको कत्ल किया है, उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया है, उनके बयानों को तोड़ा-मरोड़ा है। लेकिन उन महान क्रांतिकारियों की मृत्यु के बाद जब जनता उन्हीं की कही बातों से प्रेरित हुई, तो उसी शोषक वर्ग ने फिर उनकी प्रशंसा की, स्तुतिगान किया ताकि शोषित जनता भ्रमित हो, विपथगामी हो जाये। लेनिन ने कहा था कि मार्क्स के मामले में भी ऐसा ही हुआ। मार्क्स के जीवनकाल में शासकों द्वारा उन्हें देश-देश से निकाला गया, उनके बारे में दुष्प्रचार किया गया। फिर मार्क्स के निधन के बाद, मार्क्सवाद का प्रभाव जब लगातार बढ़ता गया, तो बुर्जुआ विचारक मार्क्स की प्रशंसा करने लगे। साथ ही वे मार्क्स के विचारों की गलत व्याख्या कर रहे हैं। नकली मार्क्सवादी भी मार्क्सवाद को विकृत कर रहे हैं, मार्क्सवाद की क्रांतिकारी प्राणसत्ता को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेनिन ने कहा कि मार्क्सवाद की इस क्रांतिकारी प्राणसत्ता को पुनर्जीवित करना होगा। लेनिन ने इस महान व्रत को न केवल पूरा किया, बल्कि मार्क्सवाद को समयोपयोगी और कई नए सैद्धांतिक योगदानों के द्वारा और भी समद्ध व उन्नत किया। इसी वजह से उनके योग्य उत्तराधिकारी महान स्तालिन ने ठीक ही कहा था, "साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रांति के युग में लेनिनवाद ही मार्क्सवाद है।" उन्होंने कहा था, "अधिक स्पष्ट रूप से कहें, तो लेनिनवाद आम तौर पर सर्वहारा क्रांति का सिद्धांत और रणनीति है और खास तौर पर सर्वहारा अधिनायकत्व का सिद्धांत और रणनीति है।" इसी मार्क्सवाद-लेनिनवाद को अवलंब बनाकर रूस, चीन और पूर्वी यूरोप में शोषणमुक्त समाज कायम हुआ था और विश्वव्यापी शक्तिशाली साम्यवादी आंदोलन गठित हुआ था।

लेनिन ने मार्क्सवाद को विकृत होने से बचाया

मैं आज की चर्चा में लेनिन की जीवनी का खास जिक्र नहीं करूंगा। मैं उनके सैद्धांतिक योगदान के कुछ पहलुओं पर चर्चा करूंगा। हेगेल के द्वंद्वात्मक भाववाद, कांट के अज्ञेयवाद और फायरबाख के मानवतावाद को परास्त कर दर्शन के क्षेत्र में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, यह मार्क्स ने पहली बार मानव जाति के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने दिखाया कि सेंट साइमन और चार्ल्स फुरिये का काल्पनिक समाजवाद भ्रांतिभरा है और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित वैज्ञानिक समाजवाद ही सही है। एडम स्मिथ व डेविड रिकार्डो के शास्त्रीय राजनीतिक अर्थशास्त्र की सीमाओं को दिखाते हुए उन्होंने यह साबित किया कि पूंजीपति केवल श्रमिकों को उनके उचित हक से वंचित करके ही मुनाफा कमाते हैं। मजदूर अपने श्रम से मालों का उत्पादन करने में जो अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है, उसका एक छोटा-सा हिस्सा उसे मजदूरी के रूप में मिलता है, बाकी मुनाफे के रूप में पूंजीपति हड़प लेते हैं। इस तरह उन्होंने और उनके सहयोगी एंगेल्स ने पूंजीवाद के क्रूर शोषणकारी चरित्र को उजागर किया। उन्होंने यह भी कहा कि इसके नतीजतन पूंजीवाद अनिवार्यत: एक गहरे संकट से रूबरू होगा और यह भविष्यवाणी की कि यह मजदूर वर्ग ही पूंजीवाद को उखाड़ फेंककर शोषणमुक्त समाज कायम करेगा। उन्होंने मानव समाज के परिवर्तन के नियमों की खोज की, जिनके आधार पर मार्क्सवाद मानव इतिहास में पहली बार शोषित लोगों के सामने शोषणमुक्त और वर्गहीन समाज की स्थापना के संघर्ष के औजार के रूप में उभरकर आया।

मार्क्स की मृत्यु के बाद एंगेल्स की उपस्थिति में जो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बना, उसका बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। लेकिन एक समय लेनिन ने देखा कि यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मार्क्सवाद को विकृत कर रहा है। लेनिन ने जीवनभर जो संघर्ष किया, उसका एक प्रमुख हिस्सा था इस विकृति के खिलाफ जोरदार संघर्ष चलाना, मार्क्सवाद की सही समझ क्या है, यह दुनिया के सामने पेश करना। अगर लेनिन ने यह अति महत्वपूर्ण काम नहीं किया होता, तो रूसी क्रांति नहीं होती, सोवियत समाजवाद नहीं होता, पूंजीवाद के विकल्प के रूप में हमें शोषणरहित समाजवादी व्यवस्था नहीं मिलती। अगर लेनिन ने यह काम नहीं किया होता, तो शायद उनके उत्तराधिकारियों के रूप में स्तालिन, माओ त्से-तुंग, शिवदास घोष भी नहीं मिल पाते। इन सभी ने मार्क्स की धारावाहिकता में लेनिन के विचारों से प्रेरित होकर ही मार्क्सवाद को समझा और उन्हीं के अनुरूप सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी संघर्ष का संचालन किया।

संगठन बनाने का प्रयास

हमारे देश में जैसे खुदीराम ने एक अत्याचारी ब्रिटिश शासक को मारने के लिए अपनी जान कुर्बान की थी, वैसे ही लेनिन के बड़े भाई का लक्ष्य भी रूस के अत्याचारी शासक जार को मारना था। वे नरोदनिक नामक एक गुट में थे, जैसे कि हमारे देश में भी स्वतंत्रता सेनानियों के ऐसे क्रांतिकारी संगठन थे। इस संगठन की सोच के अनुसार लेनिन के बड़े भाई ने रूसी सम्राट द्वितीय जार का वध करने की कोशिश की, लेकिन वे पकड़े गये और उन्हें फांसी हुई। लेनिन उस समय कमसिन उम्र के थे। इस घटना ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। वे समझ गये कि इस रास्ते से बात नहीं बनेगी। तब फिर क्या रास्ता है? वह रास्ता खोजना होगा। उस रास्ते को खोजते-खोजते बहुत कम उम्र में ही उन्हें मार्क्स-एंगेल्स की कुछ पुस्तकें मिलीं। 17 साल की उम्र में जब वे कजान विश्वविद्यालय के छात्र थे, तब वे छात्रों के जार-विरोधी जुलूस में शामिल होने के जुर्म में गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के बाद उन्हें एक गांव में नजरबंद रखा गया। वे कुछ समय तक वहां रहे। उस नजरबंदी में, सुबह से रात तक मार्क्स-एंगेल्स के जितने भी ग्रंथ वे जुटा पाये, उनका उन्होंने गहन अध्ययन किया। इस दौर के बाद लेनिन समारा नामक एक और शहर में आ गये। वहां उनके प्रयासों से पहला मार्क्सवादी अध्ययन-मंडल (स्टडी सर्कल) बनाया गया। इस दौरान रूस के विभिन्न शहरों में छोटे-छोटे मार्क्सवादी अध्ययन मंडल कायम हो गये थे। लेनिन समझ गए कि अलग-अलग अध्ययन मंडलों से काम नहीं चलेगा, सभी को एक साथ लाना होगा। जब वे 25 वर्ष के थे, तो उन्होंने रूस की राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग में मार्क्सवादी अध्ययन मंडलों को एकजुट करके 'लीग ऑफ स्ट्रगल फॉर दि इमेनसिपेशन ऑफ दि वर्किंग क्लास' (मजदूर वर्ग के मुक्ति-संघर्ष की संस्था) गठित की। बाद में उन्होंने कहा कि यह सर्वहारा पार्टी का भ्रूण था। क्रांतिकारी आंदोलन में उनकी शुरुआत इसी तरह हुई। यानी इस प्रकार उन्होंने पहली बार संगठन बनाने का बीड़ा उठाया। इसके बाद, अलहदा-अलहदा विभिन्न समूह, जो मार्क्सवाद की साधना कर रहे थे, उनमें प्रचार करने के लिए उन्होंने देश से बाहर जाकर 'इस्क्रा' (चिंगारी) नामक एक अखबार निकाला। क्योंकि देश के भीतर जार के सख्त शासन में ऐसा करना संभव नहीं था। देश में गुप्त रूप से भेजकर इस अखबार के जरिये सभी से संपर्क करना, उनके पास मार्क्सवाद की अपील पहुंचाना—यही उस समय उनका संघर्ष था। अपने शुरुआती जीवन में अपने खुद की पहलकदमी से किये गए इन सभी कार्यों ने बाद में उनकी प्रगति में एक सोपान का काम किया।

लेनिन ने पहचाना कृषि में पूंजीवाद का चरित्र

'नरोदनिक' गुट का कहना था कि रूस जैसे पिछड़े देश में, जहां मजदूरों की संख्या कम है, किसान ही जार के खिलाफ क्रांति करेंगे। इस दौरान लेनिन ने उनके खिलाफ लेख लिखकर सैद्धांतिक संघर्ष किया। इसके अलावा, उस समय 'इकोनॉमिस्ट' (अर्थवादी) नामक एक और दल यह प्रचार कर रहा था कि राजनीति करना मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवियों का काम है। मजदूर राजनीतिक आंदोलन में न रहें। वे सिर्फ अपनी आर्थिक मांगों के लिए ही लड़ें। इनके खिलाफ भी लेनिन को इस समय वैचारिक संघर्ष करना पड़ा। जब वे सेंट पीटर्सबर्ग में ये गतिविधियां चला रहे थे, वहां मजदूरों की हड़ताल को राजनीतिक रूप से दिशा दे रहे थे और सलाह-मशविरा देकर उनकी मदद कर रहे थे, तब उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान वे लंबे समय तक जेल में रहे। इसके बाद लेनिन को साइबेरिया में निर्वासन में भेज दिया गया। वे तीन साल तक वहां रहे। जब वे गांव में नजरबंद थे, तब उन्होंने किसानों की जीवन शैली और गरीबी को प्रत्यक्ष देखा। वे उनके साथ घुल-मिल गये और उन्होंने उनसे राजनीतिक चर्चा की। इसी तरह, वे सेंट पीटर्सबर्ग में मजदूरों के साथ घुल-मिल जाते थे, उनकी समस्याओं और विचारों को समझते थे और उनमें क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करते थे। साइबेरिया में रहते हुए उन्होंने 'रूस में पूंजीवाद का विकास' नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने दिखाया कि न केवल उद्योगों में, बल्कि रूस के ग्रामीण इलाकों में भी कैसे पूंजीवाद विकसित हो रहा है। यह मार्क्सवाद में उनका एक मौलिक योगदान है। यह रचना विश्व साम्यवादी आंदोलन के क्षेत्र में भी एक अमूल्य धरोहर है। इसमें लेनिन दिखाते हैं कि कृषि में पूंजीवाद घुसपैठ कर रहा है—यह क्या-क्या लक्षण देखकर समझा जाये? उन्होंने दिखाया, इसके लिए पहले तो यह देखना होगा कि जमीन बाजार में बिकाऊ माल बन गई है या नहीं। सामंतवाद में जमीन की खरीद-बेच नहीं होती थी। पूंजीवाद आया है, इसका मतलब है कि जमीन बाजार में बिकने वाले माल में तब्दील हो गयी है। दूसरे, उन्होंने

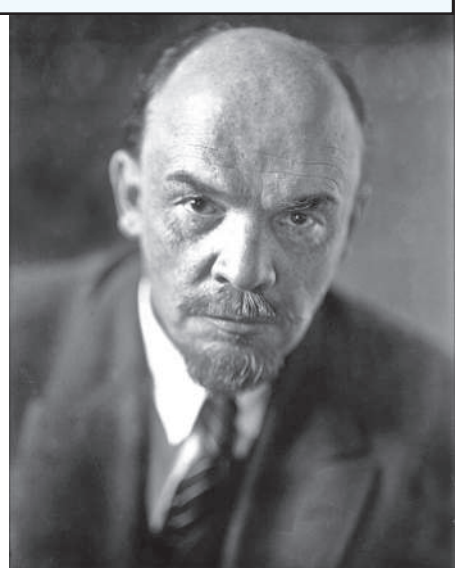

दिखाया कि पहले गांवों में एक-एक क्षेत्र में उत्पादित संपदाएं मुख्यत: क्षेत्र के उपभोग के लिए ही रखी जाती थीं। यह आत्मनिर्भर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था थी। लेकिन बाद में, जो फसल गांवों में पैदा हो रही है, वह कमोडिटी ऑफ दि नेशनल मार्केट यानी पूरे राष्ट्रीय बाजार का माल बन गयी है। यह भी पूंजीवाद का ही चरित्र है। इसके अलावा, उन्होंने दिखाया कि एक तबका मजदूरी के एवज में खेती-बाड़ी का काम कर रहा है। यानी वे खेतमजदूर अब मुजारे या भूदास नहीं हैं। ये जो कृषि भूमि बाजार का बिकाऊ माल है, कृषि उपज भी राष्ट्रीय बाजार का बिकाऊ माल है और जो मेहनत-मजदूरी कर रहे हैं, उनकी श्रम शक्ति भी बिकाऊ माल है, वे भूदास नहीं हैं। वे श्रम बेचकर मजदूरी पाते हैं, यानी वे खेत मजदूर हैं—ये गांव में सामंतवाद को खत्मकर पूंजीवाद के प्रवेश के स्पष्ट लक्षण हैं। लेनिन से पहले किसी ने इस तरह से नहीं दिखाया था। बाद में लेनिन ने यह भी दिखाया कि विकसित पूंजीवादी देश जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका में भी कृषि में सामंतवाद के अवशेष बचे हुए हैं।

'नरोदनिकों' और 'इकोनॉमिस्टों' के खिलाफ वैचारिक संघर्ष, मार्क्सवाद के प्रचार के लिए 'इस्क्रा' का प्रकाशन और रूस में पूंजीवाद के विकास संबंधी सिद्धांत—ये सभी साबित करते हैं कि उस उम्र में ही उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा को कितनी गहराई से आत्मसात कर लिया था।

पार्टी सदस्य बनने का पैमाना

प्लेखानोव, जिन्होंने पहले पहल मार्क्सवादी पुस्तकों का रूसी भाषा में अनुवाद कर रूस में प्रचार किया, जिन्हें लेनिन शुरुआती दौर में शिक्षक मानते थे, उन्हीं प्लेखानोव के प्रयासों से इस समय रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन हुआ और उसकी पहली कांग्रेस हुई। इसमें लेनिन नहीं जा सके। तब वे साइबेरिया में निर्वासित थे। पार्टी की दूसरी कांग्रेस 1903 में लंदन में हुई। उसी कांग्रेस में लेनिन के साथ अन्य लोगों के इस बात पर तीखे मतभेद थे कि पार्टी सदस्य कौन होगा। इस विवाद के आधार पर रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी (आरएसडीएलपी) में बोल्शेविक और मेन्शेविक नामक दो गुट बन गए। लेनिन ने कहा कि सदस्य वे ही होंगे, जो पार्टी का सिद्धांत मानेंगे, चंदा देंगे, अनुशासन मानेंगे, पार्टी के किसी एक संगठन में शामिल होकर रोजमर्रे के कामकाज करेंगे। जबकि मेन्शेविक, जो उनके विरोधी थे, उनका कहना था कि सदस्य पार्टी का सिद्धांत मानेंगे, चंदा देंगे, लेकिन यह शर्त नहीं होनी चाहिए कि वे पार्टी के किसी न किसी संगठन में शामिल

(शेष पृष्ठ 7 पर)

कटक (ओडिशा) : पूरे राज्य में जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ चार वाम दलों एसयूसीआई (सी), सीपीआई (एमएल), सीपीआई (एमएल-रेड फ्लैग) और सीपीआई (एमएल-न्यू डेमोक्रेसी) द्वारा प्रदर्शन।

जन शिक्षा नीति पर बैठक

पटियाला (पंजाब): ऑल इण्डिया सेव एजुकेशन कमेटी (एआईएसईसी) द्वारा 9 अप्रैल को यहां विश्व पंजाबी केंद्र, पंजाबी विश्वविद्यालय में "जन शिक्षा नीति 2026–एनईपी 2020 का एक विकल्प" पर एक गोलमेज बैठक आयोजित की गई। एआईएसईसी के महासचिव व जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता के सेवानिवृत्त प्रो. तरुण कांति नस्कर ने चर्चा की शुरुआत की, जबकि एआईएसईसी पंजाब के सचिव अमिंदरपाल सिंह ने बैठक का संचालन किया।

इसके अलावा, कार्यक्रम में प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रो. रणजीत सिंह घुमन, प्रख्यात लेखक डॉ. दर्शन सिंह अष्ट, शिक्षाविद् हरजीत सिंह बाजवा, मशहूर अभिनेता इकबाल गुज्जन, सेवानिवृत्त लेक्चरर राम कुमार, हरदीप सिंह, गुरबचन सिंह, सिंह सभा के हरजोत, केंद्री सिंह सभा के डॉ. खुशाल सिंह, प्रो. शाम सिंह, डीटीएफ नेता तलविंदर, हरिंदर, रविंदर, सामाजिक कार्यकर्ता रोम सिंह, वेदप्रकाश टापा, अमरदीप, थाना सिंह, पारस दीप, जसविंदर और एडवोकेट शिवाशीष प्रहराज ने भाग लिया।

विभिन्न शैक्षिक समस्याओं पर विभिन्न जिलों में सेमिनार आयोजित करने और जन-हितैषी, जनवादी शिक्षा नीति अपनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को सामूहिक प्रतिनियुक्ति देने का निर्णय लिया गया।

शिक्षण शिविर का आयोजन

घाटशिला (झारखंड) : ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) की बिहार राज्य परिषद की ओर से 2 से 4 अप्रैल 2026 तक यहां मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष विचार अध्ययन केंद्र में तीन दिवसीय शिक्षण शिविर उत्साह-उमंग और जोशो-खरोश के साथ संपन्न हुआ।

इस शिविर में 17 जिलों के लगभग 300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और वाद-विवाद, गीत-संगीत, खेलकूद तथा वैचारिक चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी करते हुए पूरे शिविर को जीवंत बना दिया।

कार्यक्रम की शुरुआत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड सौरव घोष द्वारा झंडोत्तोलन एवं कॉमरेड शिवदास घोष की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। इसके बाद संगठन के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सचिव कॉ. मणिशंकर पटनायक ने शिक्षण शिविर के उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

शिविर की आधार पुस्तक "क्या छात्रों को राजनीति करनी चाहिए?" पर दो सत्रों में गंभीर और प्रेरक चर्चा हुई। इन सत्रों में कॉ. सौरव घोष ने क्रांतिकारी विचारों, महापुरुषों के जीवन-संघर्ष और वर्तमान समय की चुनौतियों को जोड़ते हुए प्रतिनिधियों को जागरूक किया तथा बेहतर इंसान और संघर्षशील छात्र बनने का आह्वान किया।

समापन सत्र में संगठन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं एस यू सी आई (कम्युनिस्ट) के बिहार राज्य सचिव कॉ. अरुण कुमार सिंह ने अपने अनुभव साझा करते हुए छात्र आंदोलन की भूमिका पर प्रकाश डाला और संगठन के विचारों को राज्य के हर स्कूल-कॉलेज एवं विश्वविद्यालय तक ले जाने का आह्वान किया। 3 अप्रैल को सांस्कृतिक संध्या में नाटक, एकल व सामूहिक नृत्य, गीत व बांसुरी वादन की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को और भी जीवंत बना दिया, जिससे साथियों में संघर्ष और बदलाव के प्रति नई ऊर्जा का संचार हुआ।

प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. सौमित्र बनर्जी ने विज्ञान प्रेमी छात्र प्रतिनिधियों से संवाद कर उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में वैज्ञानिक सोच अपनाने का आह्वान किया।

शिविर का संचालन बिहार राज्य अध्यक्ष कॉ. विजय कुमार, उपाध्यक्ष कॉ. राजू कुमार एवं कॉ. शिव कुमार व राज्य सचिव कॉ. पवन कुमार को लेकर चार सदस्यीय अध्यक्षमंडल ने किया। इस मौके पर केंद्रीय परिषद सदस्य सह झारखंड राज्य सचिव कॉमरेड सोहन महतो भी उपस्थित रहे।

गुड़गांव और नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के आंदोलन के समर्थन में आयी एआईयूटीयूसी

हरियाणा

गुड़गांव, मानेसर, फरीदाबाद, पलवल आदि औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों पर पुलिस दमन बंद कराने व उनकी लंबित मांगों को पूरा कराने के बारे में 18 अप्रैल को ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी) की ओर से गुड़गांव, सोनीपत, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़े आदि जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर जिला उपायुक्त कार्यालयों की मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गये। ज्ञापन में एआईयूटीयूसी ने अपनी प्रमुख मांगों में न्यूनतम वेतन को महंगाई के अनुरूप बढ़ाने, कार्यस्थलों पर मूलभूत सुविधाएं और सुरक्षा सुनिश्चित करने, मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार पर रोक लगाने, गिरफ्तार श्रमिकों की तत्काल रिहाई, घायल मजदूरों के इलाज व मुआवजे तथा श्रम कानूनों के सख्ती से पालन की मांग की।

भिवानी में एआईयूटीयूसी के जिला सचिव कॉमरेड राजकुमार बासिया के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल में जिला प्रधान कॉमरेड धर्मवीर सिंह, संदीप मेहरा, सुखबीर सिंह, रामेहर, राजेराम, अनिता, सरोज, सुनील, युवी सहित अन्य साथी शामिल थे।

सोनीपत उपायुक्त कार्यालय पर धरना दिया गया और मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन ने भी अपनी 17 मांगों का ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम दिया। वक्ताओं में एआईयूटीयूसी के राज्य सचिव कॉमरेड हरिप्रकाश, उपाध्यक्ष कॉमरेड ईश्वर सिंह राठी, जिला सचिव कॉमरेड बलबीर सिंह, जिला प्रधान कॉमरेड बलवान सिंह, ब्रह्म सिंह दहिया आदि प्रमुख थे।

रेवाड़ी में एआईयूटीयूसी के राज्य अध्यक्ष कॉमरेड राजेन्द्र सिंह, जिला सचिव कॉमरेड शेर सिंह व अन्य साथियों के नेतृत्व में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया।

गुड़गांव में एआईयूटीयूसी, जिला कमेटी गुड़गांव द्वारा मजदूरों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय की मार्फत ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल में श्रमिक नेता कॉमरेड श्रवण कुमार गुप्ता, बलवान सिंह, कॉमरेड रामकुमार और कॉमरेड वजीर सिंह शामिल थे।

मजदूर नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर मजदूरों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया और दमनात्मक कार्रवाइयों पर रोक नहीं लगी, तो आने वाले समय में एआईयूटीयूसी आंदोलन और तेज करने को बाध्य होगा।

मध्य प्रदेश राज्य का राजनैतिक शिक्षण शिविर सम्पन्न

भोपाल (मध्य प्रदेश): एसयूसीआई (सी) की मध्य प्रदेश राज्य कमेटी की ओर से 27-28-29 मार्च 2026 को तीन दिवसीय राज्य स्तरीय राजनैतिक शिक्षण शिविर का आयोजन राजधानी भोपाल में किया गया। इसके लिए सभी को 'मार्क्सवाद मानव समाज के विकास पर', 'वैचारिक सांगठनिक सवालों पर' और 'मौजूदा खास हालात में नेता-कार्यकर्ताओं का विशेष कर्तव्य' किताबें अध्ययन करने को कहा गया था।

राजनैतिक शिक्षण शिविर का संचालन एसयूसीआई (सी) के पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड सोमेन बसु, केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड अरुण कुमार सिंह और पार्टी के मध्य प्रदेश राज्य सचिव सह केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड प्रताप सामल ने किया।

शिक्षण शिविर की शुरुआत में कॉमरेड शिवदास घोष पर रचित गीत प्रस्तुत किया गया। इसके बाद शिविर में भाग लेने वालों द्वारा रखे गये विभिन्न सवालों पर चर्चा हुई। शिक्षण शिविर के अंत में अंतर्राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया गया। इस तरह जोरदार नारों के साथ शिक्षण शिविर सम्पन्न हुआ।

ज्योतिबा फुले की 199वीं जयंती पर आम सभा

दिल्ली: सामाजिक शोषण-उत्पीड़न के खिलाफ व समानता के लिए बुलंद आवाज महान मनीषी महात्मा ज्योतिबाराव फुले की 199वीं जयंती पर शहीद व मनीषी यादगार मंच, त्रिलोकपुरी की तरफ से 12 अप्रैल को आमसभा की गई। आम सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय आम लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर जे मुर्मू और मुख्य वक्ता मास्टर गिरिवर सिंह थे। डॉक्टर आशना, अध्यापिका द्रोपदी बैरवा, बाबू लाल आदि ने कार्यक्रम में अपनी बात रखी। आमसभा के कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती संध्या विश्वकर्मा और सभा अध्यक्ष श्रीमती बासमती थीं।

स्कूल बचाओ संघर्ष यात्रा निकाली

गुना (मध्य प्रदेश) : प्रदेश के 94 हजार सरकारी स्कूल बंद करने की नीति के खिलाफ स्कूल बचाओ संघर्ष समिति द्वारा यहां 16 से 20 मार्च पांच दिवसीय स्कूल बचाओ संघर्ष यात्रा निकाली गयी। इस यात्रा के दौरान पूरे गुना शहर में पांच दिन तक यात्रा ने घूमकर शिक्षक-छात्र-अभिभावकों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की।

अपनी ज्वलंत मांगों के लिए संघर्ष की राह पर आशा वर्कर

दिल्ली : 8 अप्रैल को दिल्ली सचिवालय पर आशा कर्मियों के धरने को ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस), दिल्ली की राज्याध्यक्ष कॉमरेड सीता सिंह और उपाध्यक्ष शारदा दीक्षित ने संबोधित किया।

मध्य प्रदेश में अनेक महिलाएं और बच्चियां लापता

एसयूसीआई (सी) ने विरोध प्रदर्शन कर जताया रोष

गुना (मध्य प्रदेश) : मध्य प्रदेश से प्रतिदिन 130 महिलाएं और बच्चियां लापता होती हैं। सरकार उचित कदम उठाने के बजाय, अश्लीलता, अपसंस्कृति और नशे को बढ़ावा दे रही है।

मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में 2 लाख 70 हजार से ज्यादा महिलाओं और बच्चियों यानी प्रतिदिन 130 महिलाओं व बच्चियों के लापता होने की घटनाओं के खिलाफ 25 मार्च को जिलाव्यापी विरोध दिवस के आह्वान पर शहर के छः प्रमुख स्थानों केंट चौराहा, टीआईटी कॉम्प्लेक्स चौराहा, बूढ़े बालाजी चौराहा, महावीरपुरा गौशाला, नानाखेड़ी पिपरौदा, मेडिकल बगीचा, श्रीराम कॉलोनी व आरोन नगर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किये गए। इस मौके पर कॉमरेड लोकेश शर्मा, कॉमरेड शोभना श्रीवास्तव, कॉमरेड विकास बंसल आदि वक्ताओं ने संबोधित किया।

इस मौके पर पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि आज हमारे समाज में अश्लीलता, अपसंस्कृति व नशाखोरी को मुनाफा कमाने के जरिये के तौर पर देखा जा रहा है। समाज के लिए हानिकारक इन व्यसनों पर जमकर मुनाफा कमाया जा रहा है और अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए मानव तस्करी, विशेषकर महिलाओं व बच्चियों को यौनता के दलदल में धकेलते हुए इसे एक व्यापक उद्योग के रूप में देखा जा रहा है। तमाम नीति-नैतिकता और आदर्शों को ताक पर रखकर महिलाओं और छोटी-छोटी बच्चियों को इसका शिकार बनाया जा रहा है।

पूरे देश में महिलाओं और बच्चियों पर यौन अपराध व छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वहीं एक बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चियां गायब हो रही हैं। यह आंकड़ा अपने आप में डरावना है और महिला सुरक्षा पर कई सवाल खड़े करता है। पिछले 1 साल में यह स्थिति और भी भयानक हुई है। जो महिलाएं बच्चियां गायब हुई हैं, उनमें बड़ी संख्या नाबालिग बच्चियों की है।

ऐसे में महिलाओं व बच्चियों की सुरक्षा करनी है, तो अश्लीलता, अपसंस्कृति, नशाखोरी व शराबखोरी पर रोक लगाने के लिए व्यापक जन आंदोलन गठित करना होगा और स्थानीय स्तर पर प्रगतिशील जनवाद पसंद लोगों को जोड़कर मोहल्ला, गांव व शहर स्तर पर जन कमेटियां गठित करनी होंगी ताकि इन अपराधों पर तुरंत एक्शन लेकर स्थानीय प्रशासन पर इन्हें रोकने के लिए दबाव बनाया जा सके। साथ ही छात्र-युवाओं में सही नीति-नैतिकता और आदर्शों को ले जाना होगा। देश के महान मनीषियों को पुनः युवाओं के बीच आदर्श के रूप में कायम करना होगा। केवल इसी रास्ते उन पर बढ़ रहे अपराधों को रोकना सम्भव है।

एआईयूटीयूसी ने हरियाणा अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों के आंदोलन का किया समर्थन

रेवाड़ी (हरियाणा) : 17 अप्रैल को केन्द्रीय श्रमिक संगठन एआईयूटीयूसी के राज्य अध्यक्ष कॉमरेड राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने यहां हरियाणा अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल को समर्थन दिया। उनके साथ एआईयूटीयूसी के जिला सचिव कॉमरेड शेरसिंह मीरपुर व कर्मचारी नेता ओमप्रकाश शास्त्री भी थे।

कॉमरेड सिंह ने कहा कि हरियाणा के अग्निशमन कर्मचारियों की मांगें एकदम जायज हैं। उन्होंने हरियाणा सरकार से मांग की कि फरीदाबाद में ड्यूटी के दौरान दो मृतक कर्मचारियों को एक करोड़ मुआवजा दिया जाए। परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। उनकी सेवा शर्तों की एक विशेष नीति बनायी जाए। हाई कोर्ट के दिसम्बर 2025 के आदेशानुसार सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। जोखिम भत्ता सहित उन्हें सभी सुरक्षा उपकरण दिये जाएं। सरकार ने पांच साल से उनके वेतन में भी कोई वृद्धि नही की है, उसे बढ़ाया जाए।

हड़ताली कर्मचारियों ने बताया कि यहां का अग्निशमन कार्यालय का भवन बिल्कुल जर्जर हालत में है, इसे कंडम घोषित किया जा चुका है। बरसात मे इसमें पानी टपकता है। जान जोखिम में डालकर सभी कर्मचारी वहीं ड्यूटी करने को मजबूर हैं। उसके आसपास भयंकर गंदगी फैली हुई है। मक्खियों का भारी प्रकोप है, जिससे वहां पर खड़े होना भी दूभर है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन व सरकार से मांग की कि इन कर्मचारियों को कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो दी ही जायें।

जंतर मंतर पर ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

जंतर मंतर: युवा महापंचायत को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड अमरजीत कुमार

खिलाफ चर्चा का माहौल भी नहीं बचा है। श्रमिकों के जनवादी अधिकारों का लगातार हनन किया जा रहा है। हाल में लाये गए चार लेबर कोड इसका ज्वलंत उदाहरण है।

अपने संबोधन में डुटा की पूर्व अध्यक्ष प्रो. नंदिता नारायण ने कहा कि विश्वविद्यालयों में बहुत सारे पद रिक्त पड़े हैं। देशभर में लाखों लाख पद खाली हैं। उन्हें भरा नहीं जा रहा है। आज निजीकरण के इस दौर में स्थाई नौकरी का स्थान पूरी तरह ठेकेदारीकरण की प्रक्रिया ले चुकी है। आवेदक परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरते हैं, लेकिन परीक्षाएं इस अनुपात में रद्द होती हैं कि युवाओं की उम्र निकल जाती है। पीएचडी करने के बावजूद रोजगार नहीं मिल रहा है।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एआईडीवाईओ के महासचिव कॉमरेड अमरजीत कुमार ने कहा कि बेरोजगारी आज केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि मानवीय त्रासदी बन चुकी है। निजीकरण और ठेकेदारी प्रथा ने सुरक्षित पक्की नौकरी की अवधारणा को ही खत्म कर दिया है। सरकार को अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी और रोजगार को नीति के केंद्र में लाना होगा। आज युवाओं को धर्म और जाति के नाम पर भटकाने की साजिश हो रही है ताकि वे अपने वास्तविक मुद्दों-रोजी-रोटी, कपड़ा और मकान-पर बात न कर सकें। आज हमारा समाज एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में ज्योतिबा फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आदि जैसे नवजागरण काल के मनीषियों तथा भगत सिंह, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, प्रीतिलता वाद्देदार जैसे आजादी आंदोलन के क्रांतिकारियों के जीवन-संघर्ष से सीख लेते हुए एक जुझारू आंदोलन गठित करना होगा।

विभिन्न राज्यों से आये युवा नेताओं ने एक स्वर में कहा कि यह महापंचायत युवाओं की सोयी हुई चेतना को जगाने और उन्हें अपने अधिकार हासिल करने के लिए संगठित करने की कड़ी में मील का पत्थर साबित होगी।

कार्यक्रम की अध्यक्षता एआईडीवाईओ के अखिल भारतीय सचिवमंडल सदस्य कॉमरेड दिनेश मोहंता ने की।

महापंचायत के दौरान एक विस्तृत प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें देश की वर्तमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की गई।

महापंचायत का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि ज्योतिबा फुले और महान क्रांतिकारियों के आदर्शों पर चलते हुए युवा समुदाय एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण तक अपना संघर्ष जारी रखेगा।

गुड़गांव और नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के आंदोलन के समर्थन में एकजुटता दिवस

पटना (बिहार) : 16 अप्रैल को पटना जंक्शन गोलंबर पर एआईयूटीयूसी (ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर) ने गुड़गांव और नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के आंदोलन के समर्थन में अखिल भारतीय एकजुटता दिवस के मौके पर प्रदर्शन किया।

इस मौके पर एआईयूटीयूसी के बिहार राज्य सचिव कॉमरेड सूर्यकर जितेंद्र ने कहा कि गुड़गांव और नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों के मजदूरों पर पुलिस की क्रूर कार्रवाई मजदूरों के उन जायज आंदोलनों को कुचलने के उद्देश्य से की गई है, जिनमें वे वेतन वृद्धि और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। वे काम के बढ़े हुए घंटों का विरोध कर रहे हैं।

हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा सरकार को श्रमिकों के जायज आंदोलनों को दबाने के बजाय, उनका शीघ्र समाधान करना चाहिए। हम गिरफ्तार और हिरासत में लिये गए सभी श्रमिकों की तत्काल रिहाई और घायल हुए सभी व्यक्तियों को उचित मुआवजा दिये जाने की भी मांग करते हैं। उन्होंने सभी ट्रेड यूनियन संगठनों से आग्रह किया कि वे राज्य द्वारा प्रायोजित दमनकारी कार्रवाई के विरोध में तथा गुड़गांव और नोएडा के आंदोलनरत श्रमिकों की न्यायसंगत मांगों के समर्थन में एकजुट आंदोलन गठित करें।

इस मौके पर सभा को संबोधित करने वालों में एआईयूटीयूसी के बिहार राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष कॉमरेड एम के पाठक, कॉमरेड उमाशंकर वर्मा, पटना जिला सचिव कॉमरेड अनामिका कुमारी, कॉमरेड इंदु कुमारी प्रमुख थे। समर्थन में सीटू के नेता कॉमरेड अरुण मिश्रा ने भी बात रखी।

सोनीपत (हरियाणा) : 13 अप्रैल को एआईयूटीयूसी की सोनीपत कमेटी ने एक ज्ञापन हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त कार्यालय, सोनीपत के माध्यम से चंडीगढ भेजा। ज्ञापन एसडीएम, सोनीपत ने प्राप्त किया। एआईयूटीयूसी ने सरकार से मांग की कि मजदूरों की सभी मांगें

मानी जाएं। ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता निरंजन लाल व अन्यों को रात में उनके घर से उठाना ट्रेड यूनियन अधिकारों का हनन बताते हुए उनके सहित गिरफ्तार सभी श्रमिकों की बिना शर्त रिहाई की मांग की गई। मजदूरों को जीने लायक वेतन मिले-ये उनका अधिकार है। सरकार द्वारा दिये जा रहे 15,220 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन को नाकाफी बताते हुए कहा कि इससे मौजूदा महंगाई का मुकाबला करना मजदूरों के लिए नामुमकिन है।

प्रतिनिधिमंडल में एआईयूटीयूसी हरियाणा प्रदेश कमेटी के सचिव कॉमरेड हरिप्रकाश, उपाध्यक्ष कॉमरेड ईश्वर सिंह राठी व अन्य शामिल रहे।

रायपुर (छत्तीसगढ़) : एआईयूटीयूसी ने 16 अप्रैल को यहां प्रदर्शन कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चल रहे मजदूर आंदोलन के प्रति एकजुटता व्यक्त की। छत्तीसगढ़ में वेदांता पावर प्लांट में हुए हादसे में मजदूरों की मौत के मामले में पर्याप्त मुआवजा व दोषियों को सजा देने की मांग भी की गई। दोनों मामलों को लेकर ज्ञापन दिया गया।

PRGI Regn. No. 43022

भाजपा का 'राम राज'

स्थाई नौकरी है नहीं

देश में मेहनतकशों का 90 प्रतिशत असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है। इनमें से 57 प्रतिशत से अधिक लोग स्वरोजगार में लगे हुए हैं, जबकि 18 प्रतिशत लोग अवैतनिक मजदूर के रूप में पारिवारिक उत्पादन का कोई न कोई काम करते हैं। कारखाने के 42 प्रतिशत मजदूर संविदा कर्मचारी हैं। वहीं, गिग वर्कर्स यानी विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर बिना किसी निश्चित अनुबंध के या मजदूर के रूप में मान्यता प्राप्त किये बिना काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। यहां तक कि सेना में भी स्थाई नियुक्ति बंद कर मोदी सरकार ने केवल 4 साल के लिए नौकरी का प्रबंध किया है, जिसे उन्होंने 'अग्निवीर' का नाम दिया है। हालांकि प्रवासी मजदूरों की सटीक संख्या की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अनुमान है यह संख्या 15 से 20 करोड़ से कम नहीं है। (Indiadetamap.com, 02.09.2025)

देश में बेरोजगारी दर शहरी क्षेत्रों में 15 से 29 वर्ष की आयु वाले युवाओं में सबसे अधिक है। यह कुल बेरोजगारी दर से काफी अधिक है। जब देश में बेरोजगारी दर 6 या 7 प्रतिशत बतायी जाती है, तब शहरों में युवाओं में बेरोजगारी दर 16 प्रतिशत से अधिक होती है। (इंडिया टुडे, 17 जून, 2025)

उद्योग बंद हो गये

पिछले पांच वर्षों में देशभर में 2 लाख 40 हजार से अधिक कारखाने बंद हो चुके हैं। इन पांच वर्षों में 75 हजार लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) बंद हुए हैं। अकेले पिछले वर्ष ही 35 हजार कारखाने बंद हुए हैं। सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि 2024-25 में महाराष्ट्र में 8472, तमिलनाडु में 4412, गुजरात में 3148, राजस्थान में 2989, कर्नाटक में 2010 और पश्चिम बंगाल में 1548 लघु एवं मध्यम उद्योग बंद हुए हैं। (द वायर, 19.03.2025)

भारी छंटनी

लोकसभा में लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी ने बताया है कि 2022-23 में लघु एवं मध्यम उद्योग में महाराष्ट्र में 54,053, तमिलनाडु में 43,324, उत्तर प्रदेश में 33,230 और गुजरात में 22,345 मजदूरों को काम से हाथ धोना पड़ा है। (द मिंट, 25 जुलाई 2024) मंत्री ने संसद में स्वीकार किया कि पिछले 10 वर्षों में 50,000 से अधिक कारखाने बंद होने के कारण 3 लाख मजदूरों ने अपनी नौकरियां खो दीं। (द वायर, 19.03.2025)

नैनो कारखाना व औद्योगीकरण

भाजपा और सीपीआई (एम) का कहना है कि अगर पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा की फैक्ट्री होती, तो पश्चिम बंगाल में उद्योगों का तांता लग जाता! जबकि, गुजरात के सानंद में नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 लाख रुपये की नैनो कार पर लगभग 60,000 रुपये की सब्सिडी दी, लेकिन बावजूद इसके नैनो कार का उत्पादन कई साल पहले ही बंद हो गया! वहां जमीन मालिक किसानों को शुरू में टाटा की फैक्ट्री में कुछ अस्थायी नौकरियां तो मिलीं, लेकिन सालभर बाद उनकी नौकरियां छिन गयीं। सरकार ने जमीन के लिए 1200 रुपये प्रति वर्ग मील या कहीं-कहीं 90 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भुगतान किया। बाद में, इस जमीन को गुजरात औद्योगिक विकास निगम ने करोड़ों रुपये की दर से बेच दिया। (एनडीटीवी, 3.12.2017, द टेलीग्राफ, 2.6.2010, ट्रिनिटी कॉलेज स्टूडेंट अर्बन रिसर्च 15.2.2010)

डबल इंजन वाले राज्यों में भी स्कूली शिक्षा का खस्ताहाल

भाजपा शासन के तहत उत्तर प्रदेश में 27,000, राजस्थान में 19,500, महाराष्ट्र में 15,000 और गुजरात में 7,000 स्कूलों का क्लोजर और मर्जर किया जा रहा है। पिछले पांच वर्षों में, देशभर में प्राथमिक स्तर पर 65 लाख 70 हजार से अधिक बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। इनमें से अकेले गुजरात में 2025-26 शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में 2.4 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा है। असम में एक वर्ष में 1.5 लाख बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या 19,000 है। भाजपा शासित ये तीनों ही राज्य बच्चों, खासकर लड़कियों के स्कूल छोड़ने के मामले में भारत में पहले स्थान पर हैं। (आनंदबाजार पत्रिका, 17.01.2026)

डबल इंजन वाले राज्यों में भ्रष्टाचार का आलम

लखनऊ उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भ्रष्टाचार के आधार पर उत्तर प्रदेश में 2024 में होने वाली 69,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी है। मीडिया ने स्पष्ट रूप से खुलासा किया है कि गोवा में भाजपा नेता किस तरह पैसों पर नौकरियां बेच रहे हैं। (द हिंदू, 17.08.2024, बिजनेस स्टैंडर्ड, 15.11.2024)।

बिहार में परीक्षा और नौकरी घोटालों की जांच कर रहे पत्रकारों सहित कई लोगों की रहस्यमय मौतों की जांच नहीं की गयी। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला में शिवराज सिंह चौहान समेत कई भाजपा नेताओं पर सरकारी नौकरियां और चिकित्सा समेत लुभावने प्रोफेशनल शिक्षा के अवसर पाने के लिए करोड़ों रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत कई भाजपा नेताओं पर 36,000 करोड़ रुपये के राशन घोटाले में शामिल होने का आरोप है। राजस्थान में भाजपा नेता वसुंधरा राजे और ललित मोदी पर 45,000 करोड़ रुपये के खनन घोटाले का आरोप है। बैंकों से हजारों करोड़ रुपये का गबन करने वाले ललित मोदी वसुंधरा राजे की मदद से ही विदेश भागने में सफल हुए थे। राज्य पेट्रोलियम निगम के 20,000 करोड़ रुपये के घोटाले में गुजरात के कई भाजपा नेता और मंत्री शामिल हैं। (स्रोत: आनंदबाजार पत्रिका, 10 जुलाई 2017) आरोपियों को या तो सीबीआई से क्लीन चिट मिल चुकी है या फिर जांच कई वर्षों से रुकी हुई है। गौरतलब है कि 2017 से सीबीआई और ईडी भाजपा शासित राज्यों में किसी भी भ्रष्ट भाजपा नेता या मंत्री का पता लगाने में असमर्थ रही है। वहीं, अन्य पार्टियों के भ्रष्टाचार के आरोपी भाजपा में पनाह लेकर चैन से दिन काट रहे हैं। ●

विभिन्न राज्यों में मजदूर आंदोलन की उमड़ी लहर

अप्रैल माह के दौरान गुड़गांव-मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में उभरा मजदूर आंदोलन एक स्वत:स्फूर्त असंतोष का परिणाम था, जो देखते ही देखते व्यापक औद्योगिक संघर्ष में बदल गया। यह आंदोलन मुख्य रूप से अस्थायी (कैजुअल/कॉन्ट्रैक्ट) मजदूरों के वेतन-भत्तों, बेहतर कार्य स्थितियों, सम्मानजनक व्यवहार और श्रम कानूनों के पालन की मांगों को लेकर खड़ा हुआ। मजदूर ठेका प्रथा और स्थायी प्रकृति के कार्यों में भी अस्थायी मजदूर लगाने का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले हरियाणा में पानीपत रिफाइनरी के मजदूरों ने भी इन्हीं मुद्दों को लेकर सफल हड़ताल की थी।

श्रमिकों के बड़े संघर्षों से हासिल 29 श्रम कानूनों को रद्द करके भाजपा सरकार ने चार लेबर कोड बना दिये हैं, जिनमें घोर मजदूर-विरोधी प्रावधान भरे पड़े हैं। इन लेबर कोडों में मालिकों के लिए खुलकर मजदूरों का शोषण करने का इन्तजाम किया गया है। आज राशन सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में 20-40% तक वृद्धि हुई है। एलपीजी गैस बेहद महंगी है। मकान किराया बढ़ चुका है। मजदूरों ने बढ़ती महंगाई और कम वेतन मिलना, ओवरटाइम में शोषण और अमानवीय व्यवहार आदि मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। संघर्षरत मजदूरों का आरोप है कि उन्हें दी जाने वाली मजदूरी बेहद कम है और काम का बोझ अधिक है। ज्यादातर मजदूरों को 11,000 रुपये से 12,500 रुपये तक मासिक वेतन मिलता है, जो वर्तमान महंगाई के अनुसार अत्यंत अपर्याप्त है। ओवरटाइम का भुगतान डबल रेट के बजाय सिंगल रेट पर किया जाता है, जो श्रम कानूनों का सरासर उल्लंघन है। मजदूरों के अनुसार प्रबंधन द्वारा मनमाने ढंग से मजदूरों को नौकरी से निकालने और गेट बंद कर देने की धमकी दी जाती है और अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। कार्यस्थलों पर सुरक्षा का कोई पुख्ता प्रबंध नहीं है। मजदूरों की शिकायतों की अनदेखी की जा रही है।

2 अप्रैल को मानेसर स्थित होंडा कंपनी कैजुअल मजदूर अचानक हड़ताल पर चले गए। यह आंदोलन पूरी तरह स्वत:स्फूर्त था। 3 अप्रैल को प्रबंधन, ठेकेदार और मजदूरों के बीच वार्ता हुई, जिसके बाद एक समझौता हुआ। इसमें प्रमुख मांगों मुफ्त केंटीन सुविधा, 100 रुपये रात्रि भत्ता, 5000 रुपये वेतन वृद्धि, डबल ओवरटाइम, बोनस एवं अन्य सुविधाओं पर सहमति और समझौते के बाद मजदूर अपनी ड्यूटी पर लौट गए। इस दौरान श्रम विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे।

होंडा में हुए समझौते की जानकारी अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों तक तेजी से पहुंची, जिससे प्रेरित होकर कई कंपनियों के मजदूर हड़ताल पर चले गए। इस तरह 3-5 अप्रैल को यह आंदोलन अन्य जगहों पर फैल गया। इनमें प्रमुख रूप से शामिल थीं: रुचिका गारमेंट्स, सत्यम ऑटो, मुंजाल शोवा, रूप पॉलिमर और ऋचा एक्सपोर्ट लाइन। 5 अप्रैल तक ऋचा के अन्य पांच प्लांट, मोडलामा और फैशन यूनिट के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हो गए। इस प्रकार आंदोलन पूरे औद्योगिक क्षेत्र में फैल गया।

5 अप्रैल की शाम तक पुलिस ने मजदूरों को फैक्ट्री गेटों से हटाकर तहसील कार्यालय के सामने बैठा दिया। यहां प्रशासन और श्रम विभाग के अधिकारियों ने मजदूरों से अलग-अलग समूहों में बातचीत की। मजदूरों को समूहों में अंदर बुलाया गया और दबाव बनाने की कोशिश की गई। बाहर मजदूर नारेबाजी करते रहे। इस समय तक ट्रेड यूनियन काउंसिल (टीयूसी) या अन्य प्रमुख यूनियन नेता मौके पर नहीं पहुंचे थे। 7 अप्रैल को केन्द्रीय श्रमिक संगठन एआईयूटीयूसी समेत विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। प्रारंभ में कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से भी पहुंचे। बाद में सीटू के नेता भी पहुंचे और पुलिस की मौजूदगी में सभा को संबोधित किया। उसी रात पुलिस ने मजदूरों को उनके घरों से उठाया और हिरासत में लिया। उनसे लिखित में लिया गया कि वे आंदोलन से दूर रहेंगे। उन्हें चेतावनी देकर अगले दिन छोड़ दिया गया। 8 अप्रैल को हरियाणा सरकार ने 10 साल बाद न्यूनतम वेतन रिवाइज कर न्यूनतम वेतन वृद्धि की घोषणा की। जबकि हर 5 साल बाद न्यूनतम वेतन में संशोधन करना होता है। प्रशासन ने मजदूरों से कहा कि उनकी मांगें मान ली गई हैं और वे काम पर लौट जाएं। साथ ही धारा 163 लागू करने की घोषणा भी की गई। जब मजदूर फैक्ट्रियों में पहुंचे और वेतन वृद्धि का नोटिस लगाने की मांग की, तब ऋचा प्लांट में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इससे भगदड़ और अफरातफरी मची। कई मजदूर घायल हुए। 70-80 मजदूरों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। उसी दिन फिर से कुछ मजदूरों को घरों से उठा लिया गया। लाठीचार्ज की सूचना के बाद एआईयूटीयूसी, एटक और सीटू के प्रतिनिधि जिला प्रशासन से मिले।

मजदूरों की मांगें कोई नाजायज नहीं हैं। इनको पूरा करके समाधान किया जाना अति आवश्यक है। मगर ऐसा करने के बजाय सरकारों ने दमन चक्र, लाठीचार्ज, गिरफ्तारी, अवैध नजरबंदी, हिरासत, घरों से पकड़धर और मुकदमें दर्ज करने का रास्ता अपनाया। हड़ताली मजदूरों पर 'कानून तोड़ने वाले', 'उपद्रवी' और आंदोलन में 'असामाजिक तत्व' शामिल होने का मनगढ़ंत आरोप लगाया गया। मजदूरों को गुनहगार की नजरों से देखा जा रहा है। यह शोषण का विरोध करने के संवैधानिक अधिकार का हनन है, जो निन्दनीय है। मानेसर सेक्टर-7 थाने में लगभग 55 मजदूर गिरफ्तार बताये गये। इनमें 20 महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी सामान्य श्रमिक हैं, कोई बड़ा नेता नहीं है। मालिकों की तरफ से दो एफआईआर दर्ज करायी गयीं। 10 से 12 अप्रैल तक कई मजदूरों को काम पर नहीं लिया गया। श्रम विभाग के हस्तक्षेप से कुछ को पुन: काम मिला। 11 अप्रैल को टीयूसी ने बैठक का निर्णय लिया। 12 अप्रैल को पुलिस ने एआईयूटीयूसी के कार्यकर्ता कॉमरेड निरंजन लाल और अन्य 6 लोगों को उनके घरों से उठाया। अगले दिन शाम तक कॉमरेड निरंजन लाल को छोड़कर अन्य 6 को मुकदमा दर्ज कर मुख्य अभियुक्त बनाकर जेल भेज दिया। मानेसर क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है। बाद में 24 महिला मजदूरों को जमानत पर छोड़ दिया गया।

ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी) ने मजदूरों के बीच जाकर उनके आंदोलन को समर्थन दिया, उनकी मांगों को जायज बताया, प्रशासन से वार्ता की और प्रबंधन, विशेषकर होंडा के प्रबंधन को समझौता लागू करने को कहा।

इस बीच उत्तर प्रदेश में नोएडा में भी मजदूर आंदोलन फैल गया। राजस्थान के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में मजदूरों का असंतोष गहराता जा रहा है। मदरसन कंपनी में प्रदर्शन खत्म होने के बाद दो और बड़ी कंपनियों रिलैक्सो इंडिया और निफोन के मजदूरों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ दिया है। हजारों की संख्या में मजदूर सड़कों पर उतर आये हैं। यह आंदोलन स्पष्ट करता है कि मजदूरों का असंतोष गहरा और व्यापक है। न्यूनतम वेतन, ठेका प्रथा और श्रम कानून उल्लंघन बड़े मुद्दे हैं। आंदोलन के दबाव में उत्तर प्रदेश सरकार को भी न्यूनतम वेतन लागू करने की घोषणा करनी पड़ी। इत्तेफाक की बात है कि इन तीनों प्रदेशों में भाजपा की डबल इंजन सरकार हैं। अगर समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो भविष्य में आंदोलन और भी व्यापक व तीव्र हो सकता है।

मजदूरों के इस वीरतापूर्ण संघर्ष को सलाम है। लेकिन इतिहास गवाह है कि सरकारी घोषणा वहीं पर लागू हो पायी है, जहां पर मजदूर संगठित हैं। वे अपने संगठन के बल पर जहां, आंदोलन करते हैं, वहां मांगें मनवा पाते हैं। अन्यथा केवल सरकारी घोषणा से मजदूरों को अब तक कहीं भी कुछ हासिल नहीं हुआ है। एआईयूटीयूसी ने श्रमिकों व मेहनतकश लोगों से आह्वान किया है कि वे अपनी समस्याओं के समाधान हेतु संगठित होकर जनवादी तौर-तरीके से जोरदार संयुक्त आंदोलन गठित करें और इसके लिए हर स्तर पर अपनी जन कमेटी, संघर्ष कमेटी और यूनियन कमेटी बनायें। ■

लेनिनः...

(पृष्ठ 3 का शेष)

होकर अनुशासन मानते हुए नियमित रूप से काम करेंगे। लेनिन ने कहा कि इस तरह से कोई भी अनुशासित सर्वहारा वर्ग की पार्टी नहीं बन सकती। इसी सवाल पर पार्टी में विभाजन हो गया। बोल्शेविक का अर्थ है बहुमत, मेन्शेविक का अर्थ है अल्पसंख्यक। यहीं पर लेनिन ने पहले पहल यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि मार्क्सवादी पार्टी का सदस्य बनने का पैमाना क्या होगा और संघर्ष जारी रखा। आरएसडीएलपी एक मंच की तरह थी। उसमें बोल्शेविक भी थे और मेन्शेविक भी थे। लेनिन के पक्ष में जो थे, वे बोल्शेविक कहलाते थे। उन्होंने उन्हें मार्क्सवादी क्रांतिकारी विचारों में ढाल दिया। दूसरी ओर, मेन्शेविक थे पेटी बुर्जुआ, समझौतापरस्त ताकतें।

लेनिन ने पहचाना पूंजीवाद का साम्राज्यवादी चरित्र

जब प्रथम विश्वयुद्ध शुरू हुआ, तो युद्ध में मजदूर वर्ग की पार्टी की क्या भूमिका होगी–इसे लेकर लेनिन के साथ दूसरे अंतरराष्ट्रीय के नेताओं के तीव्र मतभेद हो गये। महायुद्ध की शुरुआत में ही साम्राज्यवाद क्या है, पूंजीवाद के किस स्तर पर साम्राज्यवाद आया, कैसे आया–मार्क्सवाद के आधार पर यह व्याख्या लेनिन ने ही पहले पहल मानवजाति के सामने प्रस्तुत की। उन्होंने दर्शाया कि पूंजीवाद के दो स्तर होते हैं। सामंतवाद को समाप्त करके पूंजीवाद का पहला स्तर प्रगति का स्तर है, प्रगतिशील स्तर है। इस स्तर पर असंख्य छोटी-छोटी पूंजी थीं। उनके बीच बेरोकटोक प्रतिस्पर्धा चलती थी। छोटे पूंजीपतियों के बीच बेरोकटोक प्रतिस्पर्धा जारी रहने के कारण छोटी पूंजी पर आधारित बहुदलीय लोकतंत्र शुरू हुआ। लेकिन एक स्तर पर कुछ पूंजीपति दूसरों को प्रतिस्पर्धा में हराकर एकाधिकारी पूंजीपति बन जाते हैं। एकाधिकारी पूंजीवाद पूंजीवाद का दूसरा स्तर है। यहां एकाधिकारी पूंजी का अर्थ है, जैसे कि इस देश में टाटा है–वह इस्पात उद्योग का भी मालिक है, वह मशीनरी बनाने वाले कारखानों का भी मालिक है, वह कोयला खदानों का भी मालिक है, वह कई उद्योगों का मालिक बन बैठा है। यह एकाधिकारी पूंजी है। छोटी पूंजी मार खाते-खाते काफी हद तक हाशिए पर आ गई है, वह जैसे-तैसे अस्तित्व बनाये रखे हुए है। कुछ उजड़ रही है, कुछ नई उभर रही है और कुछ एकाधिकारी पूंजी के हमले से परास्त हो रही है।

एकाधिकारी पूंजी के स्तर पर एक और चीज होती है। पहले बैंक जनता से पैसे लेता था और पूंजीपतियों को देता था, जनता को ब्याज मिलता था। यह बैंक-पूंजी और उद्योगपतियों की पूंजी या औद्योगिक पूंजी–ये दोनों अलग-अलग थीं। एकाधिकारी पूंजी एक स्तर पर पहुंचने के बाद बैंक पूंजी और औद्योगिक पूंजी–दोनों का विलय हो गया, यानी उनका एकीकरण हो गया। यह साम्राज्यवाद की पहली विशेषता है। इसके नतीजतन इनमें से धनकुबेर समूह या वित्तीय अल्पतंत्र उभर आया। पूंजी का सकेंद्रण हुआ, वित्तीय पूंजी का जन्म हुआ। यह उसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता यह है कि केवल औद्योगिक उत्पादों को ही नहीं, बल्कि सस्ते श्रम और सस्ते कच्चे माल की लूट के लिए वित्तीय पूंजी का विदेशों में, यानी पिछड़े देशों में निर्यात किया जाता है। चौथी विशेषता यह है कि विभिन्न देशों के एकाधिकारी पूंजीपति घराने विभिन्न देशों के बाजारों को नियंत्रित करने के लिए ट्रस्ट और कार्टेल बना लेते हैं। पांचवीं विशेषता यह है कि विभिन्न साम्राज्यवादी देश दुनिया को आपस में बांट लेते हैं।

युद्ध में मजदूर वर्ग की भूमिका

साम्राज्यवाद की ये विशेषताएं लेनिन ने दिखायी। उन्होंने दिखाया कि इस युग में युद्ध साम्राज्यवादियों के बीच बाजार हथियाने की लड़ाई है। वास्तव में युद्ध लूट के क्षेत्र पर कब्जा करने की लड़ाई है। इससे पहले, स्विट्जरलैंड के बासले में हुए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि साम्राज्यवादी युद्ध छिड़ने पर युद्धरत साम्राज्यवादी देशों का मजदूर वर्ग अपने-अपने देशों की सरकारों के खिलाफ लड़ेगा। एक देश के मजदूर दूसरे देश के मजदूरों से नहीं लड़ेंगे। इस देश के मजदूर भी सैनिक हैं और उस देश के मजदूर भी सैनिक हैं। दोनों देशों के मजदूर एक दूसरे को नहीं मारेंगे। इसे बासले मेनिफेस्टो कहा जाता है। डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुए सम्मेलन में भी यही निर्णय था। साम्राज्यवादी अपने लूट के क्षेत्र को बांटने के लिए लड़ रहे हैं। उस संघर्ष के मौके पर मजदूर अपने देश के पूंजीपति वर्ग के खिलाफ, साम्राज्यवादियों के खिलाफ लड़ेंगे, गृहयुद्ध छेड़ देंगे, क्रांति करेंगे। यह निर्णय लिया गया था।

लेकिन जब युद्ध छिड़ गया, तो 1915 में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय की बैठक जिमेरवाल्ड, स्विट्जरलैंड में हुई। बैठक में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय के अधिकतर नेताओं ने कहा कि नहीं, मजदूर वर्ग अब अपने-अपने देश की रक्षा करेगा, यानी अपने-अपने देश की सरकार के पक्ष में खड़ा होगा। यानी अपने देश के साम्राज्यवाद के पक्ष में खड़ा होगा। लेनिन ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि आप पहले के निर्णय का उल्लंघन कर रहे हैं। यह नहीं हो सकता। लेनिन-विरोधी बहुमत में थे, लेनिन अल्पमत में। लेनिन तब दूसरे अंतर्राष्ट्रीय से बाहर निकल गए। उन्होंने कहा कि ये विश्वासघाती हैं। ये मार्क्सवाद से भटककर सर्वहारा वर्ग के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीयतावाद से गद्दारी कर रहे हैं।

दूसरे अंतर्राष्ट्रीय के नेताओं में यह भटकाव क्यों आया? साम्राज्यवादी देश उपनिवेशों, अर्ध-उपनिवेशों को लूट रहे थे। वे उस लूट के हिस्से से अपने देश के मजदूरों की मजदूरी जरा बढ़ाकर, यानी मजदूरों व मजदूर नेताओं को भी रिश्वत देकर उनका रोष शांत कर दे रहे थे। लेनिन ने कहा कि दूसरे अंतर्राष्ट्रीय के नेता उन मजदूर नेताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो साम्राज्यवादियों से रिश्वत खा रहे हैं और खरीद लिये गये हैं। वे क्रांति के खिलाफ जा रहे हैं। इस तरह, देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सही मार्क्सवादी लाइन की रक्षा के लिए लेनिन को एक ही समय में संघर्ष करना पड़ा।

सोवियतों का उदय

इससे पहले, 1905 में रूस में एक विद्रोह हुआ था। यह मजदूर वर्ग का रोष फूट पड़ने से हुआ था। एक ईसाई पादरी गैपन ने मजदूरों को समझाया कि हमारे सम्राट बड़े दयालु हैं, चलो मैं आपको उनके पास ले चलूं। आप फरियाद करना, वे सभी मांगों को मान लेंगे। मजदूर चले गए। जार की फौज ने उन पर भारी गोलीबारी की। हजारों लोग मारे गए। यह दिन 'ब्लडी सनडे' यानी 'खूनी रविवार' के तौर पर कुख्यात है। इस वजह से रूस में भारी विरोध प्रदर्शन हुए। हड़ताल पर हड़ताल शुरू हो गई। विभिन्न कारखानों में मजदूर कमेटियां बन गयीं, जिन्हें सोवियतें कहा जाता है। मजदूरों की संघर्ष कमेटियां सोवियतें पूरे देश में कई जगह फैल गईं। फौज में भी कुछ सोवियतें बन गईं। लेकिन इन्हें नेतृत्व देने लायक संगठन बोल्शेविकों का अभी तैयार नहीं हुआ था। यह क्रांति 1905-06 तक जारी रही। यह विभिन्न प्रांतों में फैल गई। जार ने फौज से नृशंस ढंग से इसे दबा दिया। लेनिन ने कहा कि इससे सबक लेना होगा। यह विफल विद्रोह अगली क्रांति के लिए एक पूर्वाभ्यास है। रूस के मजदूरों, रूस के लोगों का भावी क्रांति का प्रशिक्षण इसी लड़ाई के जरिये हुआ है। इस बीच, देश में शासक वर्ग का हमला जारी रहा। आरएसडीएलपी में भी कई लोग डर-भय और निराशा-हताशा से दूर हटने लगे। लेनिन का यहां एक प्रसिद्ध कथन है। उन्होंने कहा कि जब क्रांति का ज्वार आता है, तो कई लोग उस ज्वार में बहकर पार्टी में शामिल हो जाते हैं, नाम कमाने के लिए, करियर बनाने के लिए। जब क्रांतिकारी आंदोलन किसी विकट संकट से रूबरू होता है, तभी असली परीक्षा होती है–कौन असली है और कौन नकली। इस पहलू पर वे एक मूल्यवान सीख सबके सामने रख गये हैं। जब पार्टी का बहुत प्रभाव-प्रतिष्ठा होती है, तो कई लोग आते हैं। लेकिन जब पार्टी गहरे संकट में होती है, जब पार्टी हमले का सामना कर रही होती है, तो जो लोग उसकी अगुआई कर रहे होते हैं, वे ही सच्चे क्रांतिकारी हैं। यही क्रांतिकारियों की परीक्षा है।

कुछ दार्शनिक भ्रम-भ्रांतियों के जवाब में

रूस में जब मायूसी छायी हुई थी, मार्क्सवाद के खिलाफ एक तरह का और हमला शुरू हुआ। बाजारोव, बोगदानोव और कुछ अन्यों ने एम्पिरियो-क्रिटिसिज्म या पॉजिटिविज्म यानी अनुभवसिद्ध आलोचना और प्रत्यक्षवाद का प्रचार करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि मनुष्य अपनी ज्ञानेन्द्रियों (सेन्स ऑर्गन) के द्वारा जो कुछ भी महसूस करता है, वही रीयल यानी वास्तविक है। यानी जिसकी इंद्रिय द्वारा अनुभूति न हो, तो वह वास्तविक नहीं है। इस कथन का मतलब है कि अगर इंद्रियों से अनुभव नहीं हो, तो किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। इस कथन का खंडन करते हुए लेनिन ने कहा कि 'मेटिरियल वर्ल्ड एग्जिस्ट इण्डिपेंडेंट ऑफ ह्युमेन कॉन्शसनेस' यानी भौतिक जगत का अस्तित्व मानवीय चेतना से स्वतंत्र है। संवेदना ज्ञान का स्रोत नहीं, बल्कि जरिया है। ज्ञान का स्रोत भौतिक जगत है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि अलकतरा से एलिजरिन पाया गया था, लेकिन यह पाये जाने से पहले ही, यानी इंद्रिय शक्ति द्वारा जानने से पहले ही अलकतरा में था। ऐसे कुछ और भ्रांत सोच-विचारों की चर्चा करते हुए उन्होंने 'मैटीरियलिज्म एंड एम्पिरियो क्रिटिसिज्म' पुस्तिक में मार्क्सवाद की सटीकता को दर्शाया। विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्होंने एक और गलत धारणा का सफाया करते हुए सही विचार क्या होना चाहिए, यह दिखाया। विद्युत-चुंबकीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर पता चला कि जैसे-जैसे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यानी गति बढ़ायी जाती है, वैसे-वैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ने लगता है। फिर इलेक्ट्रॉनों की गति जितनी कम होती जाती है, उनका द्रव्यमान उतना ही कम होने लगता है। इस तरह घटते-घटते एक समय ऐसा लगता है कि द्रव्यमान नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन अब नहीं है। इसलिए भ्रमित होकर वैज्ञानिकों का एक समूह कहता है कि 'मैटर डिस्अपियर हो गया', यानी अब पदार्थ नहीं रहा। इसके जवाब में लेनिन ने कहा था कि पदार्थ गायब नहीं हुआ है, बल्कि पदार्थ संबंधी इससे पहले की धारणाओं की सीमा गायब हो रही है और पदार्थ के बारे में ज्ञान और गहरा हो रहा है। पहले वाली धारणा अपरिवर्तनीय नहीं थी, सापेक्ष थी। बाद में विज्ञान ने लेनिन के इस कथन की सत्यता साबित कर दी।

शुरू में लेनिन प्लेखानोव को अपना शिक्षक मानते थे। वे कहते थे, 'प्लेखानोव रूस में मार्क्सवाद के जनक हैं'। क्योंकि प्लेखानोव ही रूस में मार्क्सवाद से संबंधित पुस्तकें लाये थे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे काउत्स्की को भी शिक्षक मानते थे। इसके बावजूद, मार्क्सवाद और सर्वहारा क्रांतिकारी आंदोलन के हित में, जिन्हें उन्होंने कभी शिक्षक माना था, उनके खिलाफ भी वे दृढ़ता और साहस के साथ वैचारिक संघर्ष चला पाये थे और दुनिया के सामने मार्क्सवाद की सही समझ पेश की थी। कितना बड़ा महान क्रांतिकारी होने पर यह उनके लिए संभव हो सका! यह वही समय था जब लेनिन ने कहा था कि वे मार्क्सवाद को सुधारने के नाम पर विकृत कर रहे हैं और मार्क्सवाद की गलत व्याख्या कर रहे हैं। तब से ही संशोधनवाद शब्द का प्रयोग होता आ रहा है।

सृजनशील मार्क्सवादी थे लेनिन

लेनिन के साथ इन सभी का फर्क समझना होगा। ये सभी मार्क्स-एंगेल्स की किताबें पढ़ चुके थे, उन्हें किताबें कंठस्थ थीं, वे किताबों से उद्धरण दे सकते थे। लेकिन ये मार्क्सवादी पंडित, विद्वान थे, जबकि लेनिन सृजनशील मार्क्सवादी थे। उन्होंने विज्ञान को समझकर मार्क्सवाद को किन परिस्थितियों में कैसे लागू करना है, अभ्यास के माध्यम से इसे हासिल किया। वे बात-बात पर कहते थे कि मार्क्स ने यह कहा है, मार्क्स ने वह कहा है। मार्क्स की काफी सारी बातें साम्राज्यवाद से पहले के युग की हैं, जो साम्राज्यवाद के युग में अब लागू नहीं होती हैं। लेनिन कहते हैं कि हम किसी भी तरह मार्क्सवादी सिद्धांत को पूर्ण और अनुलंघनीय जैसा कुछ नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्क्सवाद की सारी बातें समाप्त हो गई हैं, मार्क्सवाद विज्ञान के रूप में अब और विकसित नहीं होगा। मार्क्स के समय उन परिस्थितियों में जो कुछ भी कहा गया था, वह सब कुछ अभी भी लागू है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता– यह भी ठीक नहीं है। यह लेनिन का प्रसिद्ध कथन है। कितने बड़े सृजनशील मार्क्सवादी होने से यह बात कही जा सकती है! उन्होंने कहा था कि मार्क्स-एंगेल्स ने केवल उस विज्ञान की आधारशिला रखी है, जिसे समाजवादियों को अगर वे जीवन के साथ तालमेल बनाये रखना चाहते हैं, तो सभी दिशाओं में विकसित करना चाहिए। जो लेनिन ने खुद किया था। यहीं पर प्लेखानोव और काउत्स्की से उनका फर्क है। वे विद्वान थे और लेनिन सृजनशील मार्क्सवादी। उन्होंने मार्क्सवादी विज्ञान, द्वंद्वात्मक भौतिकवादी विज्ञान को अपनाया और उस विज्ञान को लागू करके विशेष परिस्थितियों का विश्लेषण करके यह निर्धारित किया कि कहां क्या करना है। उन्होंने कहा कि क्रांति की मात्र आम लाइन (दिशा-निर्देशक मूल सिद्धान्त), जिस तरह से इंग्लैंड में लागू होगी, फ्रांस में नहीं होगी, जिस तरह से फ्रांस में होगी, जर्मनी में नहीं होगी, जिस तरह से जर्मनी में होगी, रूस में नहीं होगी। प्रत्येक देश में कुछ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विशेषताएं होती हैं। इसलिए सर्वहारा क्रांति से तात्पर्य एक आम लाइन से है, पूंजीवाद के खिलाफ सर्वहारा क्रांति। एक-एक देश में, देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार इस क्रांति की लाइन तय करनी होगी। इसे कंक्रिटाइजेशन ऑफ मार्क्सिज्म (मार्क्सवाद का विशेषीकृत रूप) कहा जाता है। यह बात लेनिन द्वारा कही गई एक ऐतिहासिक बात है।

प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और रूसी जार थे। दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी थे। इस युद्ध के दौरान लेनिन रूस की सरजमीं पर प्रचार कर रहे थे ताकि ब्रिटिश और फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों के साथ जार का जो समझौता है, उसका स्वरूप देश के मेहनतकशों को समझ में आ सके। वे मेहनतकशों को समझाते हैं कि उन्हें जार शासन के खिलाफ क्रांति करनी चाहिए। लेनिन की शिक्षा के जरिये बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में रूसी मेहनतकशों को इस तरह से तैयार किया जा रहा था। इस समय लेनिन के साथ काउत्स्की, प्लेखानोव, मेन्शेविकों और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय के नेताओं के मतभेद दिखाई दिये। उन्होंने कहा कि सबसे उन्नत पूंजीवादी देश में पहले क्रांति होगी और वह भी एक साथ कई देशों में। यह पहले के दिनों की सोच थी। लेनिन ने कहा कि साम्राज्यवादी युग में यह संभव नहीं है। साम्राज्यवादी युग पूंजीवाद के असमान विकास का युग है। इसके अलावा, ये नेता बुर्जुआ संसदीय राजनीति के मोह में पड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि भले ही यह देश अविकसित है, लेकिन अब जिस देश में संकट सबसे अधिक है और जिसके कारण विरोध जहां सबसे अधिक है, उसी देश में क्रांति की जा सकती है और एक देश में ही क्रांति करना संभव है। दूसरों ने कहा कि रूस अब बुर्जुआ जनवादी क्रांति के स्तर पर है और क्रांति बुर्जुआ वर्ग के नेतृत्व में होगी। लेनिन ने कहा कि आज के समय में भी यह बुर्जुआ जनवादी क्रांति बुर्जुआ के नेतृत्व में पूरी नहीं होगी, मजदूर वर्ग को इस क्रांति में नेतृत्वकारी भूमिका निभानी होगी।

(शेष अगले अंक में)

PRGI Regn. No. 43022

गुरुग्राम व नोएडा में सरकार की दमनात्मक कार्रवाई का विरोध

गुड़गांव और नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरों पर पुलिस की बेरहमी से की गई कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए एआईयूटीसी के महासचिव कॉमरेड शंकर दासगुप्ता ने 14 अप्रैल, 2026 को जारी बयान में कहा:

"ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी) की अखिल भारतीय कमेटी गुड़गांव और नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया के मजदूरों पर पुलिस की बेरहमी से की गई कार्रवाई की कड़ी निंदा करती है। यह कार्रवाई मजदूरों के जायज आंदोलनों को दबाने के लिए की गई है, जो वेतन बढ़ाने, काम के घंटे न बढ़ाने और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा सरकारों को मजदूरों के न्यायसंगत आंदोलनों को जबरदस्ती दबाने के बजाय, मजदूरों की लंबे समय से लंबित जायज मांगों को जल्द पूरा करना चाहिए। हम सभी गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मजदूरों की तुरंत रिहाई और सभी घायल लोगों को इलाज व उचित मुआवजा देने की भी मांग करते हैं।

एआईयूटीयूसी अपनी सभी संबद्ध यूनियनों और जिला और राज्य संगठनों से अपील करता है कि वे मालिकों और सरकारों की बेरहमी से की गई कार्रवाई के खिलाफ पूरे देश में विरोध कार्यक्रम आयोजित करके गुड़गांव और नोएडा के मजदूरों के न्यायसंगत आंदोलनों के साथ एकजुटता दिखाएं।

हम सभी ट्रेड यूनियनों से यह भी अपील करते हैं कि वे सरकार द्वारा उठाये गये दमनात्मक कदमों के विरोध में और गुड़गांव और नोएडा के आंदोलनकारी मजदूरों की जायज मांगों के पूरे समर्थन में संयुक्त आंदोलन गठित करें।"

जनप्रिय नेता कॉमरेड विजय पाल सिंह की अवैध नजरबंदी का ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन ने किया कड़ा विरोध

रोहतक।

ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड सत्यवान और ऑल इण्डिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी) के अखिल भारतीय सचिवमण्डल सदस्य कॉमरेड आर.के. शर्मा ने ने 17 अप्रैल को जारी बयान में केन्द्रीय श्रमिक संगठन, एआईयूटीयूसी के उत्तर प्रदेश राज्य अध्यक्ष एवं मुरादाबाद के पीतल मजदूरों के सर्वप्रिय नेता कॉमरेड विजय पाल सिंह को गत 16-17 की अर्द्धरात्रि से उनके घर में नजरबंद रखने का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि तमाम मेहनतकशों को ऐसी मनमानी दमनात्मक कार्रवाई का विरोध करना चाहिए।

गौरतलब है कि कॉमरेड विजय पाल सिंह के नेतृत्व में 17 अप्रैल को एआईयूटीयूसी की ओर से महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम एक ज्ञापन मुरादाबाद के उपायुक्त को सौंपना था, जिसमें उत्तर प्रदेश के नोएडा में अपनी न्यायसंगत न्यूनतम मजदूरी जैसी निहायत जायज मांग के लिए संघर्षरत मजदूरों पर दमनकारी कार्रवाई बन्द करने और नाजायज गिरफ्तार मजदूरों को रिहा करने की मांग उठाई जानी थी। परन्तु उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी सरकार को इतनी-सी बात भी सहन नहीं हुई। इसीलिए कॉमरेड विजय पाल सिंह को कल रात से घर में नजरबंद किया हुआ है। यह जनता के न्यूनतम जनतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का शर्मनाक फासीवादी कदम है।

एआईकेकेएमएस और एआईयूटीयूसी की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की गयी कि कॉमरेड विजय पाल सिंह को नजरबंदी से तुरन्त मुक्त किया जाए और प्रदेश में श्रमिकों के शोषण-दमन पर रोक लगायी जाए, उनकी जायज मांगों को पूरा किया जाए और नाजायज गिरफ्तार मजदूरों को रिहा किया जाए।

किसान नेता प्रकाश मल्लिक की अवैध गिरफ्तारी का विरोध

कटक (ओडिशा) : एआईकेकेएमएस ने संगठन के प्रमुख नेता और राज्य के केओंझर जिले के पटना ब्लॉक, जो बंदूक की नोक पर जबरन भूमि हड़पने के खिलाफ जनउभार का केंद्र था, के लोगों के बेदखली-विरोधी ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेता की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ 2 अप्रैल को राज्यव्यापी विरोध दिवस मनाया। एआईकेकेएमएस ओडिशा राज्य कमेटी के आह्वान पर पटना ब्लॉक के जमुनापोसी गांव सहित राज्य के विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किये गए, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और प्रकाश मल्लिक की तत्काल बिना शर्त रिहाई की मांग की।

उल्लेखनीय है कि ओडिशा के केओंझर जिले के पटना ब्लॉक के हजारों आम लोग, ज्यादातर आदिवासी, अपने घरों, चूल्हों और हजारों हेक्टेयर सिंचित दोफसली कृषि भूमि, वन भूमि और वन को बचाने के लिए डबल इंजन भाजपा-नीत राज्य सरकार और जिंदल-पोस्को जैसे कॉर्पोरेट घरानों के संयुक्त हमले के खिलाफ एक गंभीर, जीवन-मरण की लड़ाई में लगे हैं। पिछली बीजेडी-नीत राज्य सरकार के शासनकाल में मेगा स्टील प्लांट लगाने के उद्देश्य से उसी जमीन को स्टील दिग्गज आर्सेलर मित्तल को सौंपने का प्रयास किया गया था। एआईकेकेएमएस के नेतृत्व में स्थानीय लोगों द्वारा लगातार, गौरवशाली

कटक

और लगभग दस साल तक चले लंबे आंदोलन के सामने कंपनी और तत्कालीन बीजेडी सरकार को पीछे हटना पड़ा, जिसमें कॉमरेड प्रकाश मल्लिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। लेकिन वर्तमान भाजपा-नीत राज्य सरकार द्वारा पिछले विधानसभा चुनाव में सत्ता संभालने के बाद फिर से उस क्षेत्र के लोगों पर मुसीबत टूट पड़ी है। पहले जिंदल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को प्राथमिकता दी गयी और बाद में प्रस्तावित इस्पात संयंत्र लगाने के दिखावटी उद्देश्य के लिए पोस्को को शामिल किया गया। इस क्षेत्र की उपजाऊ जमीन को जबरन हड़पने के बजाय, जिले में उपलब्ध विशाल गैर-कृषि योग्य जमीन पर प्रस्तावित इस्पात संयंत्र लगाने के लिए स्थानीय लोगों की दलीलें सुनने से इनकार कर दिया गया। एकाधिकारी पूंजी का स्वार्थ साधने के लिए राज्य सरकार ने क्षेत्र में आतंक का राज कायम कर दिया है ताकि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भूमि अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों की विरोध की आवाज दबायी जा सके और जबरन जमीन हड़पने के खिलाफ शांतिपूर्ण, लेकिन सतत प्रतिरोध को तोड़ दिया जा सके। प्रस्तावित मेगा स्टील प्लांट बनाने के लिए पुलिस-प्रशासन ने लोकतांत्रिक मानदंडों की धज्जियां उड़ाते हुए क्षेत्र को दरअसल मैदाने-जंग में तब्दील कर दिया है। पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को परेशान कर रही है, महिलाओं सहित सैकड़ों लोगों पर मनगढ़ंत मामले दर्ज कर रही है, उन्हें बेबुनियाद आरोपों के तहत जेल में डाल रही है। कॉमरेड प्रकाश मल्लिक, जो लोगों के प्रतिरोध आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए कंपनी और प्रशासन की आंख की किरकिरी बन गए हैं, को माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अग्रिम जमानत के बावजूद, आधी रात में धरपकड़ कर हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया ताकि वे लंबे समय तक जेल में रहें और लड़ाकू लोगों का मनोबल तोड़ दिया जाये।

एआईकेकेएमएस राज्य अध्यक्ष कॉमरेड सदाशिव दास और सचिव कॉमरेड रघुनाथ दास ने कॉमरेड मल्लिक की बिना शर्त रिहाई की मांग पर बड़ी संख्या में आगे आने पर राज्य के लोगों को बधाई दी है और जिंदल-पोस्को के साथ समझौता रद्द करने का आह्वान किया है।

'लोकतंत्र के ठेकेदार' अमेरिकी शासकों द्वारा की जा रही लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ अमेरिका में विशाल विरोध प्रदर्शन

'हमें तानाशाही नहीं चाहिए, राजशाही नहीं चाहिए, लोकतंत्र चाहिए।' 'ट्रंप नहीं, हम लोग ही अंतिम बात कहेंगे।' 29 मार्च को अमेरिका के न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लॉस एंजिल्स, टेक्सास, बोस्टन, फिलाडेल्फिया, मिनियापोलिस, डलास, शिकागो, पोर्टलैंड सहित 50 शहरों में ऐसे ही नारे गूंजे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आप्रवासन नीति, युद्ध नीति और बढ़ती महंगाई के खिलाफ लाखों लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। यह आवाज बुलंद की गयी कि राष्ट्रपति और उनके करीबी धनकुबेरों के लिए देश में कोई जगह नहीं है।

'नो किंग्स' आंदोलन के नाम से मशहूर पूंजीवाद-साम्राज्यवाद विरोधी स्वत:स्फूर्त विरोध की यह लहर तीसरी बार अमेरिका में महसूस की गई। हालांकि पिछले दो हफ्तों में इस तरह के कई प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन ट्रंप सरकार के खिलाफ इतने सारे लोगों को सड़कों पर उतरते नहीं देखा गया है। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किये गये संयुक्त हमले से अमेरिकी नागरिक नाराज हैं। उन्होंने ईरान से अमेरिकी सैनिकों की तत्काल वापसी की मांग की है। उनकी संख्या कम नहीं है, प्रदर्शनकारियों की संख्या ही इसका सबूत है।

एक तरफ, अमेरिका की अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है। अक्तूबर 2025 के आंकड़ों से पता चलता है कि देश का आर्थिक संकट बहुत घनघोर है। ऋण अधिकतम स्तर पर पहुंच गया है। लगभग 10 लाख परिवारों ने अपने घर खो दिये हैं। 2026 में फरवरी में 92 हजार लोगों की छंटनी हुई है। बेरोजगारी में कम से कम 4 फीसदी वृद्धि हुई है। 2025-26 में शिक्षा के क्षेत्र में बहुमुखी संकट का दौर चल रहा है। सरकारी स्कूल और कॉलेज-शिक्षा चौपट हो रही है। 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, 45 प्रतिशत सरकारी स्कूल कम शिक्षकों के साथ चल रहे हैं। नतीजतन, छात्रों का दाखिला कम हो रहा है और साक्षरता दर कम हो रही है। स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से चरमरा गई है। स्वास्थ्य सेवा महंगी और बीमे पर निर्भर है। इसलिए जिनके पास पैसा नहीं है, वे इलाज नहीं करा सकते। यहां भी काफी हद तक पूंजीवादी-साम्राज्यवादी देश भारत जैसा ही आलम है।

अमेरिकी साम्राज्यवाद ने युद्ध-अर्थशास्त्र का रास्ता अपनाया है ताकि वह भयानक मंदी जैसी आर्थिक परिस्थितियों से बाहर निकल सके। इस बीच, ट्रंप और उनके अमीर सहयोगियों के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों को 'एपस्टीन फाइल' में दर्ज किया गया है। ट्रम्प प्रशासन इन सब के खिलाफ लोगों के विरोध को दबाने के लिए एक के बाद एक अलोकतांत्रिक कदम उठा रहे हैं। आंदोलन करने पर विश्वविद्यालय छात्रों को जेल तक भेजा जा रहा है। ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रवासियों को पकड़ने के नाम पर हो रही ज्यादतियों के खिलाफ विभिन्न राज्यों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

मित्र इजराइयल के सहयोग से ईरान पर हमला, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी, क्यूबा पर आर्थिक नाकेबंदी और कब्जा करने की धमकी आदि के पीछे असली मकसद दुनिया में अमेरिकी धनकुबेरों के लिए बाजार सुनिश्चित करना और देश के हथियार व्यापार में और तेजी लाकर पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ाने का रास्ता आसान बनाना है ताकि बड़ी संख्या में देशी शासकों की तिजोरियां भरी जा सकें, यह दिन के उजाले में स्पष्ट है।

राष्ट्रपति की साजिश को समझकर अमेरिकी नागरिक फिर से विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। यूरोप के कई शहरों जैसे लंदन, लिस्बन और रोम में भी मेहनतकश लोगों ने साम्राज्यवादी अमेरिका के शासकों के खिलाफ मोर्चा खोला है। अमेरिकी जनता का कहना है कि हम देश को तानाशाहों के हाथों में नहीं छोड़ सकते। हम लोग अपने देश को चलाएंगे। अमेरिका में लाखों लोगों की आवाज ने इस ऐतिहासिक सच्चाई की याद दिला दी है कि 'शासकों का फरमान नहीं, जनता का आदेश ही अंतिम बात होती है।'

(स्रोत: डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. प्रोजेक्ट सिंडिकेट.कॉम, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. मियामी स्टूडेंट.नेट, फॉर्च्यून.कॉम)

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Marutinandan Printers and Publishers, Shakti Complex,6/18, Sameypur Industrial Area, Delhi-110042 and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005.
Editor: Comrade Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C). **Phone No. : 9416763089, 9868350503** Email: **sarvaharadrishtikon@gmail.com**